सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

मूर्ख व्यक्ति दूर-दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है।

वर्ष 01, अंक 251, नई दिल्ली

गुरुवार, 23 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दिल्ली में अगर लागू हुआ यह नियम तो इन बसों की एंट्री पर लग जाएगा बैन, केजरीवाल सरकार ने दी जानकारी

संजय बाटला

ग्रेप का चौथा चरण लागू होते ही CNG इलेक्ट्रिक BSVI डीजल बसों को छोड़कर अन्य सभी बसों पर दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध अपने आप लागू होंगे। जैसे ही दिल्ली में ग्रैप के चौथे चरण को रद्द किया जाता है तो यह प्रतिबंध अपने आप हट जाएगा। यह जानकारी दिल्ली सरकार के एक अधिसूचना में दी गई।

नई दिल्ली। अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत प्रतिबंध लागू होता है, तो CNG, BSVI डीजल और इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर अन्य बसों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। दिल्ली सरकार के अधिकारी गजट अधिसूचना में यह बात कही गई है।

ग्रैप-IV लागू होते ही बसों की एंट्री बैन

अधिसूचना के अनुसार, ग्रेप का चौथा चरण लागू होते ही CNG, इलेक्ट्रिक, BSVI डीजल बसों को छोड़कर अन्य सभी बसों पर दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध अपने आप लागू होंगे। गजट के मुताबिक, जब भी दिल्ली में ग्रैप का चौथा चरण लागू होगा तो अपने पास इन बसों की एंट्री पर बैन लग जाएगा।

GRAP IV हटते ही खत्म हो जाएगा प्रतिबंध

जैसे ही दिल्ली में ग्रैप के चौथे चरण को रद्द किया जाता है, तो यह प्रतिबंध अपने आप हट जाएगा। खास बात है कि पिछले महीने दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि हरियाणा से दिल्ली में एंट्री करने वाली सभी बसों को इलेक्ट्रिक, सीएनजी या BSVI डीजल पर चलाना होगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से दिल्ली में आने वाली बसों को इसका पालन करना पड़ेगा।

सीएम योगी का तोहफा: परिवहन निगम के ड्राइवर-कन्डक्टर का बढ़ा पारिश्रामिक, जानिए अब किस दर से होगा भुगतान

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) अशोक कुमार ने बताया कि सीएम योगी एवं परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन निगम में कार्यरत ड्राइवरों-कन्डक्टरों की पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित किया गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे ड्राइवरों- कन्डक्टरों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने संविदा ड्राइवरों- कन्डक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आगामी 1 दिसम्बर, 2023 से ड्राइवरों-कन्डक्टरों के पारिश्रमिक में प्रति किमी 14 पैसे की दर से अधिक भुगतान किया जाएगा। इससे परिवहन निगम की बसों में कार्यरत 30 हजार से अधिक ड्राइवरों-कन्डक्टरों को लाभ मिलेगा। इस सम्बंध में प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने आदेश जारी कर दिया है।

1 दिसंबर से लागू होगी नई दर

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) अशोक कुमार ने बताया कि सीएम योगी एवं परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन निगम में कार्यरत ड्राइवरों-कन्डक्टरों की पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित किया गया है। अभी तक 1.75 रुपए प्रति किमी की दर से भुगतान किया जा रहा था, जिसे पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ाकर 1.89 रुपए प्रति किमी कर दिया गया है। नई दर से देय भुगतान 1 दिसम्बर, 2023 से लागू होगा।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि नोएडा क्षेत्र की नगरीय बसें, इसी क्षेत्र की ग्रामीण सेवाएं, एनसीआर क्षेत्र के अन्तर्गत कौशाम्बी, साहिबाबाद एवं लोनी डिपो व एनसीआर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त डिपोज की ग्रामीण सेवाओं में कार्यरत केवल संविदा चालकों, गोरखपुर क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सौनोली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज बस डिपो के संविदा चालक एवं उप नगरीय सेवाओं के ड्राइवरों को छोड़कर शेष संविदा ड्राइवर-कन्डक्टर को ही इसका लाभ मिलेगा।

क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने के कानून में बदलाव जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समीक्षा के लिए कहा

परिवहन विशेष न्यूज

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में संशोधन की कवायद के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की जरूरत होगी जिसमें समय लगेगा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को 17 जनवरी तक इस कानूनी सवाल की समीक्षा करने का निर्देश दिया कि क्या लाइट मोटर व्हीकल (हल्के मोटर वाहन) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से एक विशेष वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल (परिवहन वाहन) को चलाने का हकदार है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन की कवायद के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की जरूरत होगी जिसमें समय लगेगा।

₹हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि वह इस प्रक्रिया को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। चूंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है, हम सभी राज्य सरकारों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देते हैं।

पीठ ने कहा, ₹कार्यवाही अब 17 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की जाएगी, जिस तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि परामर्श पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले आगे के कदमों का एक स्पष्ट रोड मैप इस अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए।₹ इस पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

शुरुआत में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की ओर से एक नोट पेश किया और कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए टुकड़ों में संशोधन के बजाय एक बड़ी तस्वीर पर विचार कर रही है।

शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ से इस बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कार्यवाही स्थगित करने से इनकार कर दिया और मामले को 17 जनवरी को सुनवाई के लिए तय कर दिया। यह भी स्पष्ट किया गया कि मामले के लंबित रहने के दौरान मुकुंद देवांगन मामले में फैसला प्रभावी रहेगा।

शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है या नहीं। क्या इस कानूनी सवाल पर कानून में बदलाव की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि ये लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दे हैं। पीठ ने कहा था कि सरकार को

इस मामले पर 'नए सिरे से विचार' करने की जरूरत है, साथ ही यह भी कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने पहले इस कानूनी सवाल से निपटने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद मांगी थी कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है।

संविधान पीठ ने कहा था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना आवश्यक होगा क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था। और उन्हें निर्णय के अनुरूप करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था।

मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। पीठ ने कहा, ₹देश भर में लाखों ड्राइवर हैं जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। यह एक संवैधानिक मुद्दा नहीं है। यह एक शुद्ध वैधानिक मुद्दा है।₹ इस पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मितल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ₹यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि कानून के सामाजिक प्रभाव का भी सवाल है... सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको यह देखना होगा कि क्या इससे गंभीर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हम संविधान पीठ में सामाजिक नीति के मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते।₹ शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक बार सरकार अदालत को अपना रुख बता दे, उसके बाद संविधान पीठ में सुनवाई की जाएगी।

संविधान पीठ एक कानूनी प्रश्न पर विचार कर रही है जिसमें लिखा है, ₹क्या 'हल्के मोटर वाहन' के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर 'हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन' चलाने का हकदार हो सकता है, जो बिना लदे वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो।₹ 18 जुलाई को संविधान पीठ ने कानूनी सवाल से निपटने के लिए 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।

इसके बाद विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों के संबंध में, मोटर वाहन अधिनियम में कथित विसंगतियों पर, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलें सुनी गईं। मुख्य याचिका मेसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी। इस कानूनी सवाल ने बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान पर विभिन्न विवादों को जन्म दिया है। यह सभी एलएमवी चलाने का लाइसेंस रखने वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से जुड़े दुर्घटना के मामले हैं।

मोटर वाहन अधिनियम विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए अलग-अलग व्यवस्था प्रदान करता है। इस मामले को 8 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। यह कहा गया था कि मुकुंद देवांगन फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया था और ₹संबंधित विवाद पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

NHAI: देशभर में सभी निर्माणाधीन सुरंगों का होगा सुरक्षा ऑडिट, एनएचएआई सात दिनों में देगी रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सुरक्षा और उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करेगा। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सुरक्षा और उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करेगा। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का बयान 12 नवंबर को उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कयारा सुरंग के ढहने की पृष्ठभूमि में आया है।

बयान में कहा गया है, ₹एनएचएआई के अधिकारी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के विशेषज्ञों की एक टीम के साथ-साथ अन्य सुरंग विशेषज्ञों के साथ, देशभर में चल रही सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपेंगे।₹

लगभग 79 किमी की कुल लंबाई के साथ, 29 निर्माणाधीन सुरंगें पूरे देश में फैली हुई हैं। जिनमें से 12 सुरंगें हिमाचल प्रदेश में, छह जम्मू और कश्मीर में, दो-दो महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान में और एक-एक मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली में हैं।

एनएचएआई ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। समझौते के हिस्से के रूप में, केआरसीएल एनएचएआई परियोजनाओं के सुरंग निर्माण और ढलान स्थिरीकरण से संबंधित डिजाइन, ड्राइंग और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करेगा।

इनसाइड

काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ रहा है वजन, महिलाएं फॉलो करें ये टिप्स, तेजी से होगा वेट गेन

दुबली-पतली महिलाएं आमतौर पर वेट गेन करने के लिए अनगिनत नुस्खे आजमाती हैं, मगर हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कई बार वजन नहीं बढ़ पाता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन महिलाओं के लिए बेस्ट हो सकता है.

स्लिम एंड ट्रिम लुक कैरी करने के लिए महिलाएं कई तरीके अपनाती हैं. इसके बावजूद कुछ महिलाएं मोटापे का शिकार होने लगती हैं. तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं. अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इन चीजों को डाइट में शामिल करके आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं.

पतली और दुबली महिलाएं अक्सर अपने फिगर को लेकर टेंशन में रहती हैं. वहीं पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के बाद भी कई बार महिलाओं का वजन बढ़ने का नाम नहीं लेता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है. तो आइए ओन्लीमाईहेल्थ डॉट कॉम के अनुसार, जानते हैं वजन बढ़ाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके महिलाएं खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

प्रोटीन का सेवन करें

नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को बॉडी का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है. खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शुगर और फैट भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है, जिससे मसल्स बिल्डिंग में काफी मदद मिलती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है. ऐसे में आप पनीर, फुल क्रीम मिल्क, दही और दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल कर सकती हैं. साथ ही चिकन, अंडा, लाल मीट, मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर जैसी चीजों से आप आसानी से वेट गेन कर सकती हैं.

फैट रिच डाइट लें

वजन बढ़ाने के लिए महिलाएं फैट से भरपूर चीजों को भी डाइट में एड कर सकती हैं. ऐसे में घी, मक्खन, नट्स और गुड फैट से भरपूर चीजों का सेवन करना महिलाओं के लिए बेस्ट होता है. इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है और महिलाओं के वजन में भी इजाफा देखने को मिलने लगता है.

कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाएं

कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें बॉडी में कैलोरी इन टेक को बढ़ावा देती हैं. जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में वेट गेन करने के लिए महिलाएं आलू, शकरकंद, ओट्स, ग्रेन और ब्राउन राइस का सेवन कर सकती हैं. वहीं घी और बटर से युक्त चीजें खाने से भी वेट गेन फास्ट होने लगता है.

वजन ना बढ़ने के कारण

महिलाओं में वजन ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. दरअसल कई बार महिलाओं के शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हेल्दी डाइट लेने के बावजूद महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है और उनका वजन कम रहता है. इसके अलावा इंफ्लेमेटरी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और हाइपोथायरॉयडिजम के चलते भी महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता है।

भारत की 5 महिला खिलाड़ी, जीवन के संघर्षों से कभी नहीं मानी हार, आज दुनिया मानती है लोहा

महिलाओं का दबदबा खेल जगत में भी बढ़ा है. भारतीय खेल के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हैं, जिन्होंने तमाम परिस्थितियों के बावजूद देश का परचम दुनियाभर में फैलाया है. आज कई भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. उनकी रैंकिंग भी दुनिया की टॉप खिलाड़ियों में शामिल हो गई है. जिन खेलों में अब तक पुरुषों का दबदबा था, वहां भी महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है. 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' पर जानते हैं देश की नामी महिला खेलाड़ियों के संघर्षपूर्ण अचीवमेंट के बारे में.

विश्व महिला क्रिकेट में झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) की उपलब्धियां कम नहीं हैं. उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से ज्यादा ओवर लेने वाली दुनिया की इकलौती गेंदबाज हैं. कभी ऐसा था कि गली क्रिकेट में उनकी धीमी गेंदबाजी पर मोहल्ले के लड़के चौके-छक्के लगाया करते थे, लेकिन झूलन ने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मेहनत किया और आज उनके नाम इतने खिताब हैं. बता दें कि उन्होंने कुल 333 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं. (Image: Jhulan Goswami-Instagram)

2/5 भारतीय मुक्केबाद जमुना बोरो (Jamuna Boro) असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गाँव से ताल्लुख रखती हैं. बचपन में ही बोरो के के पिता का निधन हो गया और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अकेली मां खेती और चाय व सब्जियां बेचा करती थीं. छोटी जमुना बचपन में ही मुक्केबाद बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने मनोबल गिराने वाली कई बातें कहीं. लेनिक जमुना ने हार नहीं माना और मुक्के बा जी को ही अपना क रि य र बनाया. आज जमुना बोरो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नम्बर एक मुक्केबाज हैं और विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल रह चुकी हैं. उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है.

भारतीय मुक्केबाद जमुना बोरो (Jamuna Boro) असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गाँव से ताल्लुख रखती हैं. बचपन में ही बोरो के के पिता का निधन हो गया और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अकेली मां खेती और चाय व सब्जियां बेचा करती थीं. छोटी जमुना बचपन में ही मुक्केबाद बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने मनोबल गिराने वाली कई बातें कहीं. लेनिक जमुना ने हार नहीं माना और मुक्केबाजी को ही अपना करियर बनाया. आज जमुना बोरो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नम्बर एक मुक्केबाज हैं और विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल रह चुकी हैं. उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है.

3/5 भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. केरल में जन्मी अंजू को बचपन से ही उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीते. साल 2003 में पेरिस में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में जब अंजू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो पूरा देश हतप्रभ था. वह भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं. (Image : Anju Bobby George-Instagram)

भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. केरल में जन्मी अंजू को बचपन से ही उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीते. साल 2003 में पेरिस में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में जब अंजू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो पूरा देश हतप्रभ था. वह भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं.

4/5 असम के नागौड जिले की एथलीट हिमा दास (Hima Das) को आज कौन नहीं जानता. छोटे कद की इस भारतीय धाविका ने दुनियाभर को चौंका दिया था. महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी पुरुष खिलाड़ी के लिए भी आसान नहीं था. बता दें कि हिमा दास के परिवार में 17 लोग थे जो धान की खेती पर आश्रित थे. वह परिवार की मदद के लिए खेतों में बुआई करती थीं, लेकिन जब उनको उड़ने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी किसी के हुनर को नहीं छीन सकती. हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की.

असम के नागौड जिले की एथलीट हिमा दास (Hima Das) को आज कौन नहीं जानता. छोटे कद की इस भारतीय धाविका ने दुनियाभर को चौंका दिया था. महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी पुरुष खिलाड़ी के लिए भी आसान नहीं था. बता दें कि हिमा दास के परिवार में 17 लोग थे जो धान की खेती पर आश्रित थे. वह परिवार की मदद के लिए खेतों में बुआई करती थीं, लेकिन जब उनको उड़ने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी किसी के हुनर को नहीं छीन सकती. हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की.

5/5 भारतीय महिला खिलाड़ियों में मैरी कॉम (MC Mary Kom) का नाम कई उपलब्धियों से भरा है. खिलाड़ी ही नहीं, वो महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा श्रोत हैं. महान भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम ने महान उपलब्धियों से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है. मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है. तीन बच्चों की मां रहते हुए भी उन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया. Image : Mary Kom Instagram

भारतीय महिला खिलाड़ियों में मैरी कॉम (MC Mary Kom) का नाम कई उपलब्धियों से भरा है. खिलाड़ी ही नहीं, वो महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा श्रोत हैं. महान भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम ने महान उपलब्धियों से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है. मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है. तीन बच्चों की मां रहते हुए भी उन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया.

कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक टेक्नीक से बाल-बाल बची ब्रिटनी विलियम्स की जान, अपनी स्टोरी शेयर कर कही, ना करें 2 संकेतों को इग्नोर

कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है.कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है.

आज लोगों में कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं. कम उम्र में ही पुरुष हों या महिलाएं, हर कोई हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो रहा है. कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को समय पर ना पहचान पाने के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. हालांकि, ब्राजील की रहने वाली ब्रिटनी विलियम्स नाम की महिला की किस्मत इस मामले में अच्छी साबित हुई थी. मात्र 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था. वह अचानक बेहोश हो गई थीं और आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. दो दिनों के बाद जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था.

टूडे डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, मात्र 24 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण ब्रिटनी विलियम्स की जान जाने ही वाली थी. यह घटना वर्ष 2014 की है. पूरे 9 वर्ष बाद ब्रिटनी ने अपनी कार्डियक अरेस्ट के दौरान हुई स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित जानकारी टुडे शो में एक इंटरव्यू के दौरान साझा की है. ब्रिटनी ने शो में उन लक्षणों के बारे में भी बताया, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज़ कर दिया था. जब ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था, तो उस दौरान उन्हें कोई भी लक्षण महसूस नहीं हुए. अचानक वो बेहोश हो गईं. इंटरव्यू में वो बताती हैं कि यदि उन्हें तुरंत वहां मौजूद लोगों ने सीपीआर ना दिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती. ब्रिटनी ने शो में सीपीआर ट्रेनिंग लेने के महत्व पर भी जोर दिया.

कार्डियक अरेस्ट के संकेत

कार्डिएक अरेस्ट तब होता है, जब एलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण हृदय की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं, जिससे दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाता है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (यूएस) के अनुसार, लगभग 90% लोग जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट आता है, उनकी मौत हो जाती है. यदि सही समय पर पीड़ित को सीपीआर दे दिया जाए तो काफी हद तक जान बचाई जा सकती है. इसके लिए सीपीआर देने के बाद तुरंत ही दिल को सामान्य लय में वापस लाने के लिए डिफाइब्रिलेटर का उपयोग भी करना चाहिए. लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक समझने की गलती कर बैठते हैं. हार्ट अटैक तब आता है, जब हार्ट में ब्लॉकेज हो. हालांकि, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बिना किसी वॉर्निंग साइन के आ सकता है. लेकिन, ब्रिटनी ने कुछ लक्षणों को इग्नोर करने की भूल की जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने से पहले महसूस हुए थे.

ब्रिटनी ने किया इन लक्षणों को नजरअंदाज

ब्रिटनी ने इंटरव्यू में कहा कि जब वह काम पर थीं, तब शरीर के बाईं ओर सुन्नपन, झुनझुनी और सनसनी जैसे लक्षणों को महसूस किया था. इलाज करने के बाद पता

चला कि ब्रिटनी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम (QT syndrome) से ग्रस्त थीं. यह एक ऐसी समस्या है, जिसमें हार्टबीट तेज और अनियमित हो जाता है. अधिकतर लोग लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं. कई बार यह दवाओं के कारण भी हो सकता है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार इसे सीजर (seizure) या मिर्गी समझ लिया जाता है. इसका इलाज दवाओं और जीवनशैली में बदलाव लाकर किया जाता है.

कार्डियक अरेस्ट के कॉमन लक्षण

अचानक बेहोश होकर गिर जाना
नाड़ी का रुक जाना
सांस का रुकना
कार्डियक अरेस्ट आने से पहले सीने में तकलीफ
सांस लेने में तकलीफ महसूस करना
कमजोरी महसूस करना
दिल का तेजी से धड़कना
इस तरह के लक्षण यदि आपको कभी भी नजर आएं, तो भूलकर भी इंग्नोर ना करें. ये कार्डियक अरेस्ट आने से पहले के संकेत हो सकते हैं. अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जैसा कि ब्रिटनी के मामले में हुआ. ब्रिटनी ने भी कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर में सुन्नपन, झुनझुनी या सनसनी जैसे लक्षण महसूस किए थे, लेकिन उसने लोगों की कही हुई बातों के आधार पर इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर दिया था.

कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर का महत्व

जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो बहुत जरूरी है कि उसके पास तुरंत कोई मेडिकल हेल्प पहुंच जाए. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर (CPR) ऐसे में लाभ पहुंचाता है. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हार्ट को कम्प्रेशन देकर एक विद्युत आवेग बनाने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय दोबारा से पंप करने लगता है. ऐसे में आज हर किसी को सीपीआर देने की टेक्नीक को सीखना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप पीड़ित की जान बचाने में सफल हो सकें. ब्रिटनी विलियम्स भी अब कुछ ऐसा ही करने में जुटी हुई हैं, ताकि उन्हीं की तरह दूसरे लोगों की भी जान बच सके.

सिसोदिया का आरोप- सीबीआई नहीं दे रही चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज, कोर्ट ने एक महीना बढ़ाई न्यायिक हिरासत

परिवहन विशेष न्यूज

आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत के समक्ष सीबीआई ने कहा कि आरोपितों की ओर से इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी की जा रही है।

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत के समक्ष सीबीआई ने कहा कि आरोपितों की ओर से इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी की जा रही है। वहीं, सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई में देरी की वजह खुद सीबीआई है, क्योंकि वह अपनी जांच व आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों को कॉपी उन्हें देने में देरी कर रही है।

उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपपत्र से संबंधित पूरे दस्तावेज सीबीआई ने उन्हें नहीं उपलब्ध कराए हैं। ऐसे में वह अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय कर दी है और सीबीआई को बचाव पक्ष को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, इस दौरान सिसोदिया को भी पेश किया गया था।

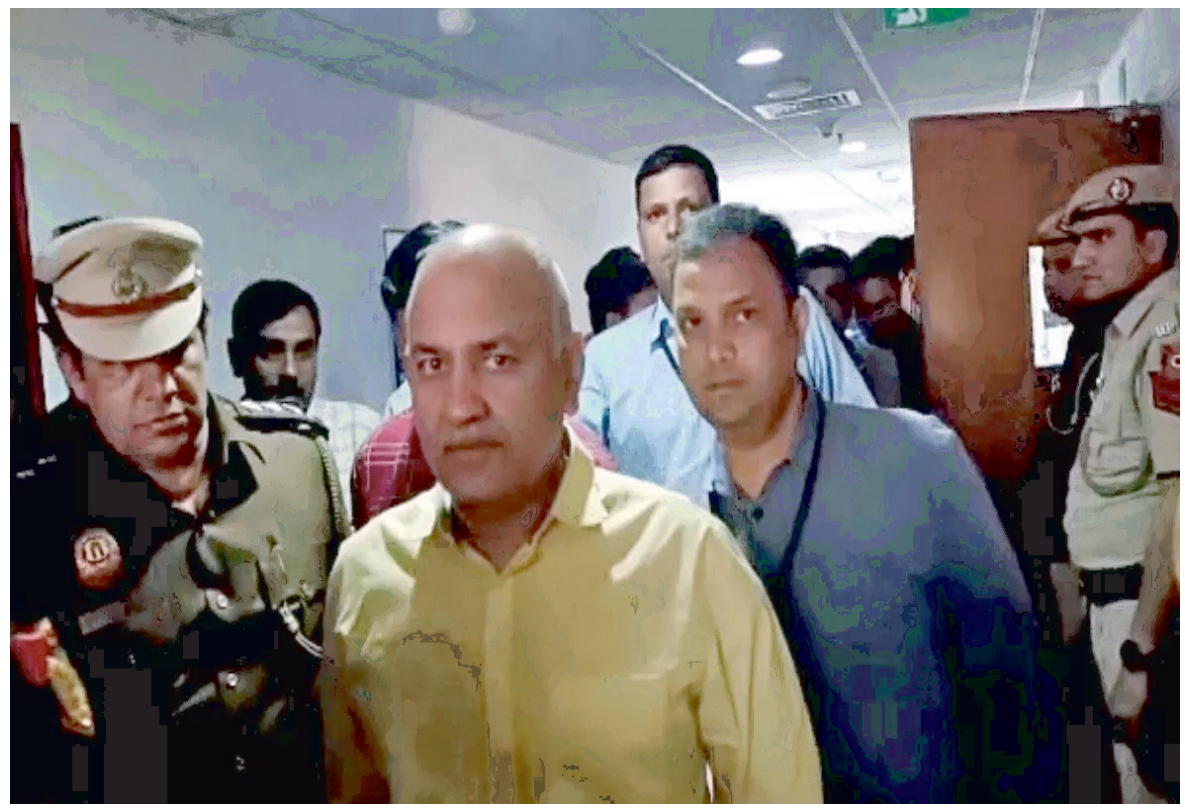

बेटे को स्कूटी पर बैठने से मना किया तो पिता ने नाबालिग को मारी गोली, पुलिस ने आरोपित को दबोचा

दिल्ली के करावल नगर में एक नाबालिग को एक लड़के को स्कूटी पर बैठने से मना करना भारी पड़ा गया। स्कूटी पर बैठने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लड़का नाराज होकर अपने पिता को बुला लिया। आरोपित नाबालिग के पिता नीरज ने पीड़ित को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस कुछ ही देर बाद पिता-पुत्र को दबोच लिया।

पूर्वी दिल्ली। करावल नगर इलाके में स्कूटी पर बैठने से मना करना 14 वर्षीय नाबालिग को भारी पड़ गया। इससे नाराज होकर स्कूटी पर बैठने वाले 16 वर्षीय नाबालिग अपने पिता को बुला लिया। पिता ने बेटे के साथ मिलकर नाबालिग की जांघ में गोली मार दी। गंभीर हालत में नाबालिग को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता पीड़ित

वारदात के कुछ देर बाद पुलिस ने शख्स व उसके नाबालिग बेटे को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपित की पहचान नीरज के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से एक पिस्टल बरामद की है। नीरज के बड़े बेटे मयंक व उसके दोस्त शिवम की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित अपने परिवार के साथ करावल नगर स्थित देवी नगर में रहता है। परिवार में माता-पिता और एक छोटा भाई है। पीड़ित घर के पास के सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। मंगलवार रात सवा आठ बजे पीड़ित 23 फुटा रोड, शिव विहार में अपने चाचा की दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान के बाहर उसके पिता की स्कूटी खड़ी हुई थी।

नाराज पिता ने नाबालिग को मारी गोली

आरोप है उसी दौरान एक नाबालिग आया और स्कूटी पर बैठ गया। पीड़ित ने उसे स्कूटी पर बैठने से मना किया। वह पीड़ित के साथ गाली गलौज करने लगा। बाद में देख लेने की धमकी देकर आरोपित वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वह अपने पिता, बड़े भाई और अन्य के साथ वहां पहुंचा।

आरोपित नाबालिग के पिता नीरज ने पीड़ित को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। कुछ देर के बाद पुलिस ने देव नगर से ही पिता-पुत्र को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह पिस्टल कहां से खरीदकर लाया था।

दिल्ली जल बोर्ड में हेरफेर करने का आरोप, भाजपा ने कहा- न्यायिक जांच की जरूरत

भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली जल बोर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने 750 करोड़ रूपये ऐसे कामों पर खर्च किये जिनका कोई प्रावधान नहीं था। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड अरविन्द केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है और इसका ऑडिट ही नहीं न्यायिक जांच की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड अरविन्द केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है और इसका ऑडिट ही नहीं, न्यायिक जांच की आवश्यकता है।

टैंकर माफिया की शिकार है दिल्ली- भाजपा

भाजपा सांसद ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में 1350 एम.जी.डी. पेय जल की आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता मात्र 950 एम.जी.डी. की है, यह खेद पूर्ण है कि लगभग 9 वर्ष के शासन में केजरीवाल ने पेय जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये हैं और दिल्ली आज भी टैंकर माफिया की शिकार है।

उन्होंने कहा कि 2016-17 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के न तो खाते बने हैं और न ही कोई ऑडिट हुआ है जो हेरफेर का बड़ा प्रमाण है। जानकारी अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड ने 750 करोड़ रूपये ऐसे कामों पर खर्च किये जिनका कोई प्रावधान नहीं था।

भाजपा ने जल बोर्ड में लगाया हेरफेर का आरोप

मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में हेरफेर का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 12 हजार करोड़ रूपये से अधिक के ठेके बिना टैंडर के 5 लाख से कम राशि के वर्क ऑर्डरों के आधार पर दे दिये गये।

वहीं, भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि सी.ए.जी. ऑडिट की मांग की थी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड आज भारत का सबसे भ्रष्ट सरकारी संस्था है, जिस पर 76 हजार करोड़ रूपये के ऐसे ऋण और अनुदान हैं जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

केजरीवाल सरकार का कोई ऐसा विभाग नही जिसके कार्यो में भ्रष्टाचार ना हो, आबकारी विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो राशन विभाग हो, परिवहन विभाग हो प्राइवेट डिस्कॉम का बिजली बिल घोटाला हो जल बोर्ड हो हर ओर हेरफेर ही हेरफेर है

पर्थला गांव में मंदिर का पिलर तोड़ने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, नोएडा प्राधिकरण का अधिकारी धुना; गाड़ियों में तोड़फोड़

नोएडा में हनुमान मंदिर तोड़ने पर गांववालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीमों ने नोएडा प्राधिकरण अधिकारी (Noida Authority Officer) और कर्मचारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ गांववालों ने मारपीट भी की। प्राधिकरण कर्मचारियों ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है। यह मामला सेक्टर-113 क्षेत्र का है जहां प्राधिकरण की जमीन पर ग्राम पर्थला में हनुमान मंदिर बना था।

नोएडा। नोएडा में हनुमान मंदिर तोड़ने पर गांववालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीमों ने नोएडा प्राधिकरण अधिकारी (Noida Authority Officer) और कर्मचारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ गांववालों ने मारपीट भी की। प्राधिकरण कर्मचारियों ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

यह मामला सेक्टर-113 क्षेत्र का है, जहां प्राधिकरण की जमीन पर ग्राम पर्थला में हनुमान मंदिर बना था। वहीं कोतवाली पुलिस का कहना है कि सेक्टर-121 पर्थला गांव के किनारे पर बने नोएडा प्राधिकरण के एक प्लॉट के छोटे कोने पर स्थानीय लोगों द्वारा करीब सात-आठ माह पहले भगवान हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति लगाई गई थी। जिसके चारों तरफ पिलर खड़े कर ऊपर स्लैब डाला गया था।

बुधवार को नोएडा प्राधिकरण की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बगैर हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर के निर्माणाधीन स्लैब को तोड़कर पिलर को गिरा दिया गया। हनुमान जी की मूर्ति को ले जाकर विसर्जित करने लगे।

इसी दौरान पर्थला गांव एवं आसपास के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। नोएडा प्राधिकरण की टीम द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को यथा स्थान पर रखकर चले गए हैं। मौके पर पर पुलिस बल मौजूद है। अन्य तथ्यों की जानकारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद समाप्त हो गया है। मौके पर अधिकारीगण एवं पुलिस बल मौजूद है।

अगर दिल्ली के इस मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो रखें ये ख्याल, HC के इस फैसले से बढ़ गया जेब पर बोझ

पैसिफिक मॉल में आने वाले लोगों को अब पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। मॉल में आने वाले लोगों से पार्किंग शुल्क नहीं लेने से जुड़ा दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) का वर्ष 2018 का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने रद कर दिया। पीठ ने कहा कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलना दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम- 2016 या दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 का उल्लंघन नहीं है।

नई दिल्ली। पैसिफिक मॉल में आने वाले लोगों को अब पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। मॉल में आने वाले लोगों से पार्किंग शुल्क नहीं लेने से जुड़ा दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) का वर्ष 2018 का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने रद कर दिया। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलना दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम- 2016 या दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 का उल्लंघन नहीं है।

फरवरी 2020 में पारित एकल पीठ के विरुद्ध पैसिफिक मॉल की अपील को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि अदालत एकल पीठ के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि पार्किंग शुल्क वसूलना बिल्डिंग बायलाज की भावना के विपरीत है।

अदालत ने कहा कि यातायात कानूनों को लागू करने में संबंधित अधिकारियों को होने वाली कठिनाई के आधार पर एमसीडी के लिए एक वाणिज्यिक उद्यम के कामकाज में हस्तक्षेप करने पार्किंग मुफ्त प्रदान करने पर जोर देने का आधार नहीं है। एमसीडी ने याचिका पर तर्क दिया कि पैसिफिक मॉल के

लिए पार्किंग शुल्क वसूलना अस्वीकार्य है क्योंकि कामर्शियल परिसर के तय फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) की गणना के लिए पार्किंग क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। एमसीडी ने दावा किया कि पार्किंग की जगह एफएआर में शामिल नहीं थी, इसलिए उक्त क्षेत्र को व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता था।

वहीं, मॉल की तरफ से तर्क दिया गया कि पार्किंग स्थलों को बिल्डिंग बायलाज के आधार पर एफएआर में शामिल नहीं किया गया था, जो अनुमेय निर्माण की सीमा निर्धारित करता है। यह भी दावा किया कि एफएआर से पार्किंग स्थानों को बाहर करने से पार्किंग स्थान पर पार्क किए गए वाहनों के संबंध में शुल्क की वसूली पर रोक नहीं लगती है। याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्णय सुनाया कि बिल्डिंग उपनियम केवल इमारतों के निर्माण के मानदंडों और मानकों से संबंधित हैं। इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि ऐसी इमारत के उपयोग से कोई मौद्रिक लाभ मिलता है या नहीं।

पति या पत्नी अगर कमाने में सक्षम हैं तो एक-दूसरे पर नहीं डाल सकते खर्चे की जिम्मेदारी, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी

परिवहन विशेष न्यूज

भरण-पोषण से जुड़े अहम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई पति या पत्नी पैसा कमाने में सक्षम है और बगैर पर्याप्त कारण के बेरोजगार रहने का चयन करता है तो दूसरे पक्ष पर भरण-पोषण के रूप में खर्च का बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने ये फैसला पति की याचिका पर दिया।

नई दिल्ली। भरण-पोषण से जुड़े अहम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई पति या पत्नी पैसा कमाने में सक्षम है और बगैर पर्याप्त कारण के बेरोजगार रहने का चयन करता है तो दूसरे पक्ष पर भरण-पोषण के रूप में खर्च का बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि भरण-पोषण का निर्णय उस पति या पत्नी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दी जानी चाहिए जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

अदालत ने उक्त टिप्पणी एक पारिवारिक अदालत द्वारा एक पत्नी को उसके पति द्वारा दायर तलाक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिए गए गुजारा भत्ते को कम करते हुए टिप्पणी की।

पति ने पारिवारिक अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें तलाक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अदालत ने उसे (पति) पत्नी को प्रति माह 30 हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। पति के वकील ने तर्क दिया कि

उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी को 21 हजार रुपये और हिंदू विवाह अधिनियम में इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया था।

पति ने अपनी कम आय का हवाला देते हुए कहा कि उसकी पत्नी दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक थी और पहले एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करते हुए 25 हजार रुपये कमाती थी, लेकिन अपीलकर्ता (पति) को अपनी बहनों, भाई और वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण करना है।

वहीं, पत्नी ने तर्क दिया कि वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और उस अस्पताल से कोई वेतन नहीं ले रही थी। वहीं, रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेज में अदालत ने पाया कि कटौती के बाद पति का वेतन केवल 56,492 रुपये थी।

वहीं, पारिवारिक अदालत ने अलग रह रही पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को बढ़ाने के लिए कोई कारण नहीं बताया है। अदालत ने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उनके कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

कमीशन के आरोप में फंसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश

इस दौरान गाजियाबाद नगर निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह की तैनाती भी हो गई उन्होंने भी पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया इस मामले की शिकायत पर मेरठ विजिलेंस द्वारा जांच भी की गई जिस्की रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना काल की शुरुआत होने के कारण डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह पर उस वक्त कोरोना की रोकथाम का जिम्मा भी था।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन खरीदने के बाद कमीशन के चक्कर मे फर्म के भुगतान में लापरवाही करने और बिल को पास न करने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में मेरठ मंडल के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर निदेशक से जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य चार साल पहले दिल्ली की मै. जितिन प्रसाद आनंद कम्प्यूटर्स फर्म को दिया गया था। कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन की खरीद भी की गई थी, जिस समय यह खरीद हुई थी, तब गाजियाबाद में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर वीरेंद्र पाल शर्मा की और स्टोर कीपर के पद पर मोहन कुमार की तैनाती थी।

फर्म ने फरवरी 2019 में लगाए थे भुगतान के लिए बिल

फर्म ने फरवरी 2019 में भुगतान के लिए बिल लगाए थे, लेकिन पत्रावलियों का अवलोकन सात माह तक भी नहीं किया गया। इस मामले में आरोप लगा था कि भुगतान से पहले कमीशन के चक्कर में पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया गया है और भुगतान के लिए बिल लेखा अधिकारी के पास नहीं भेजा गया।

इस दौरान गाजियाबाद नगर निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह की तैनाती भी हो गई, उन्होंने भी पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया इस मामले की शिकायत पर मेरठ विजिलेंस द्वारा जांच भी की गई, जिस्की रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना काल की शुरुआत होने के कारण डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह पर उस वक्त कोरोना की रोकथाम का जिम्मा भी था।

ऐसे में पत्रावलियों का अवलोकन करना मुश्किल था लेकिन यदि वह पत्रावली का अवलोकन कर लेते तो बिल का भुगतान हो जाता। उनको आपराधिक श्रेणी का तो नहीं लेकिन शिथिल पर्यवेक्षण का दोषी माना गया था और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गयी थी। अब यह मामला उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के पास पहुंचा है, उन्होंने इस मामले में जांच के निर्देश जारी किए हैं।

गले से छीनकर भाग रहे बाइक सवारों से मंगलसूत्र के लिए भिड़ गई महिला, दौड़कर पकड़ी बाइक; पैदल भागे आरोपी

सेक्टर 70ए में सुबह सैर के लिए निकली एक महिला के गले से बाइक सवार दो युवकों ने मंगलसूत्र और मोबाइल फोन छीन लिया। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए दौड़ लगाकर उनकी बाइक को पकड़ लिया। बाइक गिरी तो आरोपित पैदल ही खेतों के रास्ते भाग निकले। बादशाहपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

गुरुग्राम। सेक्टर 70ए में सुबह सैर के लिए निकली एक महिला के गले से बाइक सवार दो युवकों ने मंगलसूत्र और मोबाइल फोन छीन लिया। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए दौड़ लगाकर उनकी बाइक को पकड़ लिया। बाइक गिरी तो आरोपित पैदल ही खेतों के रास्ते भाग निकले। बादशाहपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

सेक्टर 70ए निवासी एक महिला अपने घर से अलमेडा चौक की तरफ सुबह की सैर के लिए निकली थी। घर से कुछ दूरी पर ही पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उनके गले से मंगलसूत्र झटक लिया। महिला का मोबाइल फोन भी छीन लिया। मंगलसूत्र करीब 15 ग्राम का था।

मंगलसूत्र छीनने के बाद महिला ने साहस दिखाते हुए दौड़कर उनकी बाइक को पकड़ लिया। बाइक पकड़ने के बाद महिला ने बाइक सवार दोनों बदमाशों को भी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह महिला के काबू नहीं आए। महिला के पकड़ने के दौरान बाइक गिर पड़ी तो आरोपित पैदल ही खेतों के रास्ते फरार हो गए। इस दौरान महिला के चिल्लाने पर स्कार्पियो सवार कुछ लोगों ने भी मदद की। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया। इस दौरान एक आरोपित का बैग मिला। जांच करने पर उसमें से खंजर पाया गया। पुलिस ने बाइक के नंबरों के आधार पर जांच की तो बाइक भी चोरी की मिली।

जिला अस्पताल में मोतियाबिंद आपरेशन के लिए लेंस बेचने वाला दलाल गिरफ्तार

सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के आपरेशन में जरूरी लैंस को 10 हजार में बेचने वाले दलाल को पकड़कर प्रबंधन ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गए आरोपित की पहचान सदरपुर के आबिद के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद प्रबंधन ने आरोपित को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। एक मरीज की आंख में मोतियाबिंद है।

नोएडा। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के आपरेशन में जरूरी लैंस को 10 हजार में बेचने वाले दलाल को पकड़कर प्रबंधन ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गए आरोपित की पहचान सदरपुर के आबिद के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद प्रबंधन ने आरोपित को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है।

एक मरीज की आंख में मोतियाबिंद है। बुधवार को आंख के ऑपरेशन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर मरीज के स्वजन की आरोपित से मुलाकात हो गई।

स्वजन का आरोप है कि उक्त आरोपित ने अस्पताल में आपरेशन के बाद आंख में लगने वाले लेंस की क्वालिटी को घटिया बताकर अच्छे लेंस के लिए 10 हजार रुपये देने को कहा। स्वजन ने इसकी शिकायत प्रबंधन से कर दी। प्रबंधन ने अस्पताल में मौजूद दलाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस का कहना था कि आरोपित के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली थी। लिहाजा आईपीसी की धारा-290 (लोक बाधा उत्पन्न) के तहत कार्रवाई की है। जांच में पता चला है कि आरोपित ने एक लैंस गार्ड की मदद से उसके परिचित को बेचा था। वहीं एक दो लेंस और भी अस्पताल में बेचे हैं।

इस संबंध में गार्ड से पूछताछ की थी, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। आरोपित को कोतवाली से जमानत दे दी गई। बता दे सर्जरी, नेत्र रोग विभाग में दलालों डॉक्टर्स, वार्ड ब्वॉय, नर्स से सांठगांठ कर रही है। हड्डी रोग में प्लेट व नेत्र रोग विभाग में लैंस के नाम पर मरीजों से वसूली की जाती है। जिसमें सभी का कमीशन होता है।

प्रबंधन की ओर से जांच की जा रही है कि मामले में किसी की संलिप्तता तो नहीं है। आरोप है कि डाक्टर एक पर्चे पर लेंस के बारे में लिखते हैं। सीएमएस डा. रेनू अग्रवाल का कहना है कि अस्पताल में मोतियाबिंद के आपरेशन के लिए लेंस निश्शुल्क है। कोई भी मरीज या उनके स्वजन दलालों के झांसे में न आएं। अगर को किसी तरह का प्रलोभन दें, तो जानकारी दे।

तीन लोगों ने की आत्महत्या: पिता ने डांटा तो B.Tech के छात्र ने किया सुसाइड; फांसी लगाकर छात्रा ने भी दी जान

बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र शिवम ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। जब तक सहपाठी उसके कमरे पर पहुंचे तब तक वह आत्महत्या कर चुका था। छात्र को गाना गाने का शौक था लेकिन छात्र के स्वजन नहीं चाहते थे कि वह संगीत में कैरियर आगे बढ़ाए।

ग्रेटर नोएडा। नालेज पार्क स्थित एनआइईटी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र शिवम ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। छात्र को गाना गाने का शौक था, जबकि उसके पिता चाहते थे कि वह बीटेक की पढ़ाई पर फोकस करे।

छात्र को गाना-गाने का था शौक

मौत से पहले छात्र ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली। जब तक सहपाठी उसके कमरे पर पहुंचे तब तक वह आत्महत्या कर चुका था। मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला छात्र शिवम बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसको गाना गाने का शौक था, लेकिन छात्र के स्वजन नहीं चाहते थे कि वह संगीत में कैरियर आगे बढ़ाए।

नॉलेज पार्क कोतवाली प्रभारी डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि स्वजन ने मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। जांच की जा रही है। इसके अलावा बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के अलग-अलग जगह पर छात्रा व महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना बादलपुर प्रभारी अमरेश कुमार ने बताया की प्रसादी यादव मूल रूप से नालंदा बिहार का रहने वाला है। वह एयरफोर्स के पीछे मेगा सिटी कालोनी में मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहा है।

छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

बीती रात पूरा परिवार एक कमरे में सो रहा था। उसी दौरान उसकी बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा ने किस कारण के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दी इसका अभी तक पता नहीं चला है। छात्रा का पिता जमीन बंटवारे को लेकर अपने गांव गया हुआ था।

महिला की संदिग्ध हाल में मौत

छात्रा अपनी माता व परिवार के लोगों के साथ कमरे में सोई थी। वहीं दूसरी घटना बादलपुर क्षेत्र के गांव सादोपुर की है। एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की किस कारण के चलते मौत हुई इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। महिला की मौत के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। महिला के स्वजन ने पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस उक्त घटना की जांच कर रही है।

युद्ध से किसी का भला नहीं होता, इजराइल-हमास की तरह रूस-यूक्रेन को भी

ललित गर्ग

हिंसा एवं जनसंहार तो निश्चित है पर यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युद्ध आज के विकसित मानव समाज पर कलंक का टीका है। युद्ध करने वाले और युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले किसी भी पक्ष को आज तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं मिला, जो उसे गौरवान्वित कर सके।

इजरायल-हमास के बीच जारी युद्ध किस करवट बैठेगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। डेढ़ माह से चल रहे इस युद्ध को विराम देने की कामना पूरी दुनिया कर रही है। सब शांति चाहते हैं, अयुद्ध चाहते हैं, अमन-चैन की भावना सभी के दिलों में है। लेकिन शांति एवं अयुद्ध की कामना के साथ कहीं-न-कहीं सोच में भयंकर भूल है। प्रतीत ऐसा हो रहा है बात युद्ध-विराम की हो और कार्य हों युद्ध के तो युद्ध-विराम कैसे होगा? इतने लम्बे युद्ध की विडम्बना यही है कि इजरायल पूरी ताकत लगाने के बावजूद अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया है। न तो वह हमास को खत्म कर पाया है और न ही बंधक बनाए गए अपने लोगों को छुड़ा पाया है। 47 दिन से चल रहे इस युद्ध का एक और सार तत्व जो सामने आ रहा है वह यह कि करीब चौदह हजार लोगों की मौत हो चुकी है और इससे दोगुने घायल हुए हैं। इस युद्ध की एक और बड़ी विसंगति यही है कि मरने वालों में अधिकतर आमजन, महिलाएं और बच्चे हैं। युद्ध अनिवार्य हो सकता है, फिर भी युद्ध के बारे में उसका अंतिम सुझाव या निर्णय यही है कि युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत निश्चित हो। लेकिन इस युद्ध में तो कोई भी जीतता हुआ प्रतीत ही नहीं हो रहा है।

हिंसा एवं जनसंहार तो निश्चित है पर यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युद्ध आज के विकसित मानव समाज पर कलंक का टीका है। युद्ध करने वाले और युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले किसी भी पक्ष को आज तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं मिला, जो उसे गौरवान्वित कर सके। निश्चित ही युद्ध तो बर्बादी है, अशांति है, विकास का अवरोध है, अस्थिरता है और जानमाल की भारी तबाही है। ऐसे युद्ध का अन्तिम निर्णय जब समझौते की टेबल पर ही होना है तो क्यों नहीं पहले ही टेबल पर बैठा जाये?

युद्ध तो एक आग है, जो सब कुछ भस्म कर देती है। हम इजरायल-हमास एवं रूस-यूक्रेन के युद्ध में ऐसी ही भारी तबाही, जनसंहार एवं विभीषिका देख रहे हैं। इन दोनों युद्ध से जुड़े अनेक सवाल अहम हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। दो देशों के बीच युद्ध में निर्णायक अथवा मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला संयुक्त राष्ट्र भी युद्ध समाप्त करने की अपील से अधिक कुछ नहीं कर पा रहा। भारत ने भी ऐसे अनूठे प्रयास किये, लेकिन उनकी निर्णायक भूमिका नहीं बन पायी। भले ही भारत के प्रयास सफल न हो रहे हों, लेकिन ऐसे ही प्रयासों की आज प्रासंगिकता है। इन्हीं में युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला है, जो विश्व मानवता के हित में है। भारत ने युद्ध विराम की कोशिशों के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी दर्शाया है। भारत ने लगातार पीड़ित लोगों की सहायता के लिये राहत सामग्री एवं दवाइयां भिजवाई हैं। भारत की पहल की संयुक्त राष्ट्र महासभा में रुचिरा कंबोज ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय नेतृत्व का संदेश स्पष्ट और सुसंगत रहा है। हम आतंकवाद के सभी स्वरूपों का दृढ़ता से विरोध करते हैं। इस्राइल और हमास के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जारी है, कम्बोज ने भारत के मानवीय आधार पर युद्ध विराम के प्रयासों को सराहा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उन प्रयासों की भी सराहना की है जिनका उद्देश्य तनाव कम करना और फिलीस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना है। कंबोज ने 70 टन आपदा राहत सामग्री पहुंचाने सहित फिलीस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इनमें दो

किस्तों में 17 टन दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं।

युद्ध की स्थितियां लगातार विकराल होती जा रही हैं, इस संघर्ष में एक तरफ है इजरायल की सेना और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास, जो फिलीस्तीन को फिर से जिंदा करने के पक्ष में हैं। इजरायल ने हमास को नेस्तनाबूत करने की घोषणा की है, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो-निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग-अलग गुटों में बंट गए हैं, विरोधाभासी सोच सामने आ रही है। सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ऐसे युद्ध के विनाश से उपजे हालात सदियों तक मानवता को भोगने पड़ते हैं। युद्ध भौतिक हानि एवं विनाश के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने में भी बहुत बड़ा कारण है। इससे पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाता है कि सालों तक इंसानों को शुद्ध सांस और भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक इस बात की घोषणा कई बार कर चुके हैं कि युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले कम और दुष्परिणामों का शिकार बनने वाले संसार के सभी प्राणी होते हैं। युद्ध कितना भी लम्बा चले, उसका अंत समझौते से ही संभव है, यह अन्तिम शरण प्रारंभिक शरण बननी चाहिए। इसके लिये दुनिया की महाशक्तियों को सच्चे एवं शुद्ध मन से प्रयास करने चाहिए। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अपील करने वाला अमेरिका, इजरायल को हथियार और गोला-बारूद मुहैया करवा रहा है। वहीं गोला-बारूद गाजा पट्टी के निहत्थे लोगों पर दागा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायल पर अचानक हुए हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान के नेता हमास के हमले को प्रोत्साहन और समर्थन के साथ युद्ध को आक्रामक बनाये रखने और इजरायल को ध्वस्त करने पर बल दे रहे हैं। हालातों को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि हालिया जंग के पीछे ईरान है और वो अपने मंसूबे में कामयाब होता दिख रहा है। निश्चित ही दोनों पक्षों के हजारों लोग पीड़ित होंगे, लेकिन जब धुआं शांत हो जाएगा, तो केवल एक ही देश के हित पूरे होंगे और वो देश है ईरान। इन हालातों में युद्ध को समाप्त करने की कोई भी पहल सार्थक साबित हो तो कैसे?

इजरायल-हमास की ही तरह रूस और यूक्रेन युद्ध भी 600 से अधिक दिन से चल रहा है। इस युद्ध में दस हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इस युद्ध में एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है। निःसंदेह हमास ने इजरायल पर जिस तरह की बर्बरता, क्रूरता एवं अमानवीयता की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। सवाल यह है कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में निर्दोष लोग जिस तरह से मारे जा रहे हैं, क्या बदले की कार्रवाई की आड़ में वह भी हमास जैसी बर्बरता एवं अमानवीयता नहीं है? शरणार्थी शिविरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी को तो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। यह भी बर्बरता ही है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इजरायल पर हमले के लिए हमास दोषी है, तो उसे सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन, जवाबी कार्रवाई के नाम पर निहत्थे लोगों को निशाना बनाने का तो कोई समर्थन कैसे कर सकता है? ऐसी स्थितियां तो युद्ध नीति के भी विरुद्ध हैं। हिंसा, उन्माद एवं आतंक की धरती पर शांति की पौध नहीं उगायी जा सकती। अशांत विश्व को शांति का सन्देश देने के लिये भारत को अधिक प्रयत्न करने होंगे। क्योंकि युद्ध के भयावह दुष्परिणामों से समस्त विश्व भयाक्रांत है, इसीलिये अब इजरायल-हमास और रूस तथा यूक्रेन में युद्ध-विराम की आवाज चारों ओर से उठ रही है। इन दोनों युद्धों के भयंकर कदमों के पीछे बहुत छोटे कारण, संकीर्णताएं एवं वैचारिक मतभेद रहे हैं। संसार में आज तक कोई भी अच्छा युद्ध एव बूरी शांति कभी नहीं हुई, जब शांति ही अच्छी और युद्ध ही बुरा है तो यह समझ व्यापक बननी ही चाहिए।

Royal Enfield Classic 350 को टक्कर देने आ गई Honda की धांसू बाइक, कंपनी ने जारी किया टीजर

कंपनी सीबी के लिए हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है जिसका मतलब मौजूदा Hness CB350 के सामान्य है। Hness CB350 एक नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल है जिसे होंडा द्वारा सेल किया जा जा रहा है। नई मोटरसाइकिल होंडा की लाइनअप में सबसे सस्ती 350 सीसी मोटरसाइकिल हो सकती है। ये कुल चार वेरिएंट्स DLX DLX Pro Chrome और लिगेसी एडिशन में आएगी।

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने एक नई मोटरसाइकिल का टीजर जारी किया है, जिसे वाहन निर्माता कंपनी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च करेगी। कंपनी सीबी के लिए हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है जिसका मतलब मौजूदा H'ness CB350 के सामान्य है। नई मोटरसाइकिल केवल होंडा के बिगबिंग आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाएगी।

Honda H'ness CB350

इस टीजर फोटो में एक मोटरसाइकिल को सप्लिट सीट सेटअप, एक ग्रैब रेल और स्विचगियर के साथ दिख रही है। जो जो H'ness पर है। इसके अलावा, टीज़र में निसिन कैलिपर के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक भी दिख रहा है और शॉक एब्जॉर्बर अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरह कवर किया गया है। H'ness CB350 और CB350RS के साथ प्लेटफार्म और इंजन साझा करेगी जो पहले से ही मार्केट में ब्रिकी के लिए उपलब्ध है।

Honda H'ness CB350 इंजन

H'ness CB350 एक नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल है जिसे होंडा द्वारा सेल किया जा जा रहा है। इसमें एक्सेसरीज किट का इस्तेमाल करके अनुकूलित किया जा सकता है। CB350 RS एक स्क्रैम्बलर है। क्योंकि नई मोटरसाइकिल H'ness और CB350RS के समान प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, इंजन साझा किया जाएगा। यह 350 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा जो 5,500 आरपीएम पर 21 बीएचपी और 3,000 आरपीएम पर 30 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है। ये 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

Honda H'ness CB350 कीमत

नई मोटरसाइकिल होंडा की लाइनअप में सबसे सस्ती 350 सीसी मोटरसाइकिल हो सकती है। ये कुल चार वेरिएंट्स DLX, DLX Pro, Chrome और लिगेसी एडिशन में आएगी। इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.10 लाख से शुरू होती हैं और 2.16 लाख रुपये तक जाती है। CB350RS दो वेरिएंट DLX और न्यू ह्यू एडिशन में आती है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.15 लाख रुपये से लेकर 2.19 लाख रुपये तक जाती है।

2024 KTM 990 Duke से उठा पर्दा, जबरदस्त इंजन के साथ इन फीचर्स से लैस है ये लीटर क्लास बाइक

KTM ने EICMA 2023 में All New 990 Duke को पेश कर दिया है। इसका मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड मोटरसाइकिलों से होगा। 2024 KTM 990 Duke को पावर देने वाला एक नया LC8c इंजन है जो यूरो 5+ के अनुरूप है। ये 947 सीसी पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन है। KTM 990 Duke को पूरी तरह से नए स्टील ट्यूब फ्रेम के आसपास विकसित किया गया है।

नई दिल्ली। KTM ने EICMA 2023 में All New 990 Duke को पेश कर दिया है। इसका मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड मोटरसाइकिलों से होगा। नई मोटरसाइकिल लाइनअप में 890 DUKE GP से ऊपर होगी। 990 ड्यूक का उत्पादन ऑस्ट्रिया के मैटीघोफेन में केटीएम के मेन प्लांट में किया जाएगा। फिलहाल, KTM की 990 Duke को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है। आइए, इसकी सभी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं।

इंजन

2024 KTM 990 Duke को पावर देने वाला एक नया LC8c इंजन है, जो यूरो 5+ के अनुरूप है। ये 947 सीसी, पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन है। यह पावरट्रेन 9,500 आरपीएम पर 121 बीएचपी की अधिकतम पावर और 6,750 आरपीएम पर 103 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है।

इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और राइडर क्विकशिफ्टर का विकल्प भी चुन सकता है।

स्पेसिफिकेशन

KTM 990 Duke को पूरी तरह से नए स्टील ट्यूब फ्रेम के आसपास विकसित किया गया है। सबफ्रेम एक एल्यूमीनियम डाइकास्ट भाग है, जिसमें सीट के नीचे एक एकीकृत एयरबॉक्स और एयर इंटेक होता है। इसके अलावा, स्विंगआर्म भी नया है और ट्रिपल क्लैंप जाली एल्यूमीनियम से बना है। 990 ड्यूक के पहिए 17 इंच के हैं और 1290 सुपर ड्यूक आर से लिए गए हैं, लेकिन दो तरफा स्विंगआर्म को शामिल करने के लिए थोड़ा अपडेट किया गया है। इन्हें मानक के रूप में ब्रिजस्टोन S22 टायर दिए गए हैं।

डायमेंशन

फ्रेम को सामने की ओर 43 मिमी WP एपेक्स ओपन कार्ट्रिज फोर्क्स द्वारा सस्पेंड किया गया है, जिसमें 140 मिमी का ट्रैवल है। ये कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबल के साथ आता है जिसे फोर्क्स के शीर्ष पर मौजूद क्लिकर्स के माध्यम से किया जा सकता है। पीछे की तरफ, एक WP एपेक्स मोनोशॉक है, जिसे रिबाउंड के लिए 5-क्लिक सेटिंग और मैन्युअल प्रीलोड एडजस्टमेंट के माध्यम से एडजस्ट किया जा सकता है।

टाटा अल्ट्रोज को खरीदने का शानदार मौका, कंपनी दे रही है बंपर छूट

वाहन निर्माता कंपनी अपनी कार टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर 35 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस कार की एक्स शोरुम कीमत 6.60 लाख रुपये है। इसके अलावा 5 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। ये नवंबर 2023 महीने के अंत तक वैलिड है। Tata Altroz को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है।

दिल्ली। भारतीय बाजार में टाटा की कारें सेफ्टी के लिए जानी जाती है। टाटा मार्केट में सबसे अधिक गाड़ियों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। अगर आप इस महीने टाटा की एक नई कार खरीदने की प्लैनिग कर रहे हैं तो आपको बता दें, ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि वाहन निर्माता कंपनी अपनी कार टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर 35 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस कार की एक्स शोरुम कीमत 6.60 लाख रुपये है। मार्केट में टाटा अल्ट्रोज की बात करें तो बलेनो और ग्लैंजा को टक्कर देने वाली प्रीमियम हैचबैक कार पर 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 10 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके अलावा 5 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। ये नवंबर 2023 महीने के अंत तक वैलिड है।

Tata Altroz सेफ्टी रेटिंग

Tata Altroz को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इस कार में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वे कंट्रोल मिलता है।

Tata Altroz इंजन

इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल -सीएनजी और 1.5 लीटर डीजल का ऑप्शन मिलता है। इसके इंजन को 5 स्पीड यूनिट के साथ जोड़ा गया है। इसे 6 स्पीड का डीसीए ट्रांसमिशन केवल 1.2 लीटर एनए पेट्रोल तक सीमित है। इसके इंजन को RDE और BS6 फेज-2 एमिशन नॉर्म्स में अपडेट किया गया है।

ठंड ने दे दी दस्तक तो विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग से ऐसे पाएं निजात, अपनाएं ये टिप्स

Car Driving Tips धुंध के समय ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को सड़क पर कम दिखाई देता है। कार विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है तापमान जो ठंड के मौसम में काफी कम हो जाता है। कार की विंडशील्ड पर जमी फॉग को हटाने के लिए अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते हैं तो कार की खिड़कियों को खोल सकते हैं।

नई दिल्ली। ठंड ने अब दस्तक दे दी है। इस मौसम में कार चलाने में काफी दिक्कत होती है। जिसके कारण सड़क हादसा भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धुंध के समय ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को सड़क पर कम दिखाई देता है। इसके साथ ही कार के विंडशील्ड पर जमा भाप भी इसका कारण बन जाती है। आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिसे अपनाकर आप आराम से इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

क्यों जमती है फॉग

कार विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है तापमान जो ठंड के मौसम में काफी कम हो जाता है। कार के बाहर के तापमान कम होने और अंदर के तापमान के अधिक होने के कारण जब ठंडी हवा विंडशील्ड से टकराती है तो वो भाप बन जाती है जिसके कारण कार विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है। जिसके कारण हादसे भी हो जाते हैं।

कार में हटीर चलाएं

अगर कार के विंडस्क्रीन पर भाप जम जाती है तो कार के हीटर को चालू कर सकते हैं। इससे कार के अंदर मौजूद की नमी खत्म हो जाती है। इसके कारण भाप कम जमेगी।

ठंड में एसी चलाएं

कार में एसी सर्दी और गर्मी दोनों में काम आता है। कई बार विंडशील्ड पर फॉग जमने की स्थिति में कार के एसी को चलाकर अंदर और बाहर के तापमान को एक जैसा करना पड़ता है। जिससे विंडशील्ड पर जमने वाले फॉग को कम किया जा सकता है।

कार की खिड़कियां खोलें

कार की विंडशील्ड पर जमी फॉग को हटाने के लिए अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते हैं तो कार की खिड़कियों को खोल सकते हैं। जिसके कारण आप फॉग जमा होने वाली समस्या से निजात पा सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान अगर आपकी कार के विंडशील्ड पर फॉग जमती है तो आप अपनी कार की चारों खिड़कियों को खोल सकते हैं।

वैदिक शिक्षा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

डा. वरिंदर भाटिया

वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है, लेकिन आजादी के बाद वैदिक ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है जिसका नतीजा समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार हाल ही में वेदों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई गई हैं।

नैतिक मूल्यों में गिरावट को देखते हुए आज वैदिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाए जाने की जरूरत है। यह शाश्वत सत्य है कि वैदिक शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्य रहे हैं, जिनकी आज बहुत जरूरत है। इनमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कार्यक्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास और विरासत व संस्कृति का संरक्षण शामिल हैं। नई शिक्षा नीति-2020 में इन बिन्दुओं पर व्यापक ध्यान दिया गया है। हमारे छात्रों को शानदार शिक्षा परंपराओं को आत्मसात करने में और अधिक सक्षम बनाने के लिए वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यूं भी वैदिक शिक्षा सुशासन के सिद्धांतों का स्टोर हाऊस है। इन सिद्धांतों को शिक्षा में जोड़ कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है'

वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है, लेकिन आजादी के बाद वैदिक ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है जिसका नतीजा समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार हाल ही में वेदों को शिक्षा प्रणाली से जोडने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई गई हैं। यह धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक इसका उपयोग भारतीय भाषाओं और वेदों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोडने के लिए किया जाएगा। वेद और भारतीय भाषाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं इसी माह से शुरू की जा रही हैं। गौरतलब है कि वैदिक शिक्षा पर आधारित बोर्ड से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने वाले छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के पात्र होंगे। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। यानी वैदिक बोर्ड से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने वाले छात्र एमबीबीएस और इंजीनियरिंग समेत किसी भी कॉलेज में तय क्राईटेरिया के अनुसार आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा नामित निकाय, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित है। वैदिक शिक्षा सांस्कृतिक दृष्टि पर बल देती थी।

इसके मुताबिक शिक्षित व्यक्ति को साहित्य, कला, संगीत आदि की समझ होनी चाहिए, उसे जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान भी होना चाहिए। पूर्वजों की परंपरा और संस्कृति की रक्षा शिक्षित व्यक्ति का कत्र्तव्य था। वैदिक शिक्षा से समस्त देश में कुछ ऐसे आधारभूत मूल्यों की स्थापना हुई जो आज भी सांस्कृतिक एकता के आधार हैं। कुछ लोगों के अनुसार आज की शिक्षा प्रणाली में यह एक आऊटडेटेड विचार समझा जा सकता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनेक गुण थे। इन गुणों का तत्व आज भी प्रासंगिक है। वैदिककालीन शिक्षा निःशुल्क थी, गुरुकुल में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके आवास, वस्त्र तथा भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। वैदिक काल की शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति शासन, धनाढ्य लोगों तथा भिक्षाटन एवं गुरु दक्षिणा से की जाती थी। वैदिककालीन शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता था। वैदिककालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक था। वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था और इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाता था। हमारी आज की शिक्षा में आध्यात्मिक तत्व न होने के कारण हमारे दिलो-दिमाग से सामाजिक संवेदना विलुप्त होती जा रही है। वैदिककालीन शिक्षा में उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। अनुकरण, व्याख्यान, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तर, तर्क, विचार-विमर्श, चिंतन-मनन, सिद्धिध्यासन, प्रयोग, नाटक एवं कहानी इत्यादि वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियों का विकास किया जा चुका था। इनको पुनः हमारे शिक्षण में शामिल करने की जरूरत है। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्यों का जीवन अत्यंत संयमित और अनुशासित होता था। उनकी जीवनशैली सादा जीवन व उच्च विचार पर आधारित थी। वैदिककालीन शिक्षा में गुरु तथा शिष्यों के मध्य मधुर संबंध थे। दोनों के मध्य स्नेह तथा श्रद्धा का संबंध था।

दोनों एक-दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखते थे तथा शिक्षकों के बीच मानस पिता-पुत्र के संबंध थे। क्या आज ऐसे रिश्ते वांछित नहीं हैं? वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुलों का पर्यावरण अति उत्तम था। गुरुकुल प्रकृति के स्वच्छ वातावरण से युक्त स्थलों में होते थे, जहां जन कोलाहल नहीं था तथा जल और वायु शुद्ध प्राप्त होती थी। आज हम छात्रों को किन हालात में शिक्षित कर रहे हैं? वस्तुतः मशीनों के जरिए दी जा रही शिक्षा मनुष्य रूपी छात्रों को असंवेदनशील रोबोट के रूप में विकसित कर रही है। यहां पर सांस्कृतिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैदिककालीन जीवन पद्धति संस्कार प्रधान थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली पूर्णतया दोष रहित थी, ऐसा कहना कठिन है, वैदिककालीन शिक्षा में राज्य का नियंत्रण या उत्तरदायित्व नहीं था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, जो पूर्णतः गुरुकुलों तक सीमित थी। अतः इससे जन शिक्षा की अवहेलना होती थी। वैदिककालीन शिक्षा में आय की सुनिश्चित एवं विधिवत व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वैदिककालीन शिक्षा का व्यय राजा, धनी लोग, भिक्षाटन तथा गुरु दक्षिणा से पूरा किया जाता था, किंतु इन सबका कोई निश्चित समय, मात्रा के न होने से असमंजस की स्थिति रहती थी। वैदिक जमाने की तरह आज भी अमरीका और अनेक देशों में उच्च शिक्षा संस्थाओं की रिसर्च फंडिंग अमीर लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहां की स्थिति दयनीय है। वैदिककालीन शिक्षा में रटने पर विशेष बल दिया जाता था।

यद्यपि उस समय उत्तम शिक्षा विधियों का विकास हो चुका था, किंतु लिखने की समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण याद रखने पर विशेष बल दिया जाता था। वैदिककालीन शिक्षा की अनुशासन व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। स्वामी दयानंद जी, महात्मा हंसराज जी व महात्मा आनंद स्वामी जी इत्यादि अनेक वैदिक कर्मयोगियों से प्रेरित पूरे देश में कार्यरत डीएवी व आर्य समाज से जुड़ी संस्थाएं वैदिक परचम को शिक्षा के जरिए गतिशील रखने के लिए इस समय डॉ. पूनम सूरी जी (पदमश्री अलंकृत) है, के नेतृत्व में निरंतर अच्छा काम कर रही है। नैतिक मूल्यों में गिरावट को देखते हुए आज वैदिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाए जाने की जरूरत है। यह शाश्वत सत्य है कि वैदिक शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्य रहे हैं, जिनकी आज बहुत जरूरत है। इनमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कार्यक्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास और विरासत व संस्कृति का संरक्षण शामिल हैं। नई शिक्षा नीति-2020 में इन बिन्दुओं पर व्यापक ध्यान दिया गया है। हमारे छात्रों को शानदार शिक्षा परंपराओं को आत्मसात करने में और अधिक सक्षम बनाने के लिए वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यूं भी वैदिक शिक्षा सुशासन के सिद्धांतों का स्टोर हाऊस है। इन सिद्धांतों को शिक्षा में जोड़ कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। अतः समाज में नैतिकता की स्थापना के लिए वैदिक शिक्षा जरूरी है।

संपादक की कलम से

अंगारों पर कुछ कदम

बदलती सदी के तमाशों के बीच स्वाभिमान की भिन्न लड़ाइयों के मध्य इनसान और नागरिक समाज के सामने सरकारों के अवतरण। एक बार फिर हिमाचल अपनी ही पड़ताल में घायल स्वाभिमान की खातिर अपने अधिकारों के आगे बौना और असहाय खड़ा है। इस बार फेहरिस्त में वाइल्ड फ्लावर हॉल के स्वामित्व को लेकर पुनः प्रदेश अंगारों पर चल रहा है। बाईस साल से प्रतीक्षारत हिमाचल जब वाइल्ड फ्लावर हॉल के भीतर प्रवेश करता है, तो चंद घंटों में यह मुलाकात भी असरदार नहीं होती, नतीजतन कदम पीछे लेने पड़े। कानूनी तौर पर हिमाचल के अस्तित्व से जुड़ी कई संपत्तियां आज भी हिमाचल की होकर भी, किसी न किसी चंगुल में फंसी हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल भी इनमें से एक है और जिसके ऊपर अपने हक की प्राप्ति के लिए सरकारें लगातार अदालत से न्याय मांग रही हैं। एक उत्साहवर्धक निर्णय आया भी तो स्टे के पंजे में फंस गया। पर्यटन की दृष्टि से यह संपत्ति राज्य के लिए रोमांच पैदा करती है। एक उच्च स्तरीय रैंकिंग के साथ वाइल्ड फ्लावर हॉल होने का अर्थ, हिमाचल के पर्यटन निगम को मालामाल कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि सरकारी उपक्रम ऐसी संपत्तियों से राज्य के खजाने का संबल बन जाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था, निपुणता तथा कौशल पैदा हो जाए, तो तमाम सार्वजनिक होटल इकाइयां पर्यटन का दस्तूर बदल दें। बदलने के लिए प्रदेश के तमाम डाक बंगले अगर पर्यटन से गठजोड़ कर लें तो करीब ढाई हजार संपत्तियां अपने हवाले से सैलानियों को बार-बार नई जगह पर बुलाने का न्यौता दे सकती हैं।

खैर वाइल्ड फ्लावर हॉल एक स्वप्निल कहानी है जो यथार्थ में हिमाचल के पर्यटन संबोधन का सीना चौड़ा कर सकती है। हिमाचल दरअसल ऐसी जमीन का टुकड़ा है, जहां कहीं पंजाब पुनर्गठन की बुर्जियां अतिक्रमण कर रही हैं, तो कहीं पूर्ववर्ती लीज के तहत बांटी गईं संपत्तियों का अधिकार तरस रहा है। पंजाब से हिमाचल में आकर मिले पर्वतीय क्षेत्र केवल जमीन की सीमा नहीं, बल्कि पर्वतीय आत्मसम्मान का अधिकार भी था। पंजाब में से 7.19 प्रतिशत हिस्सा इस तरह सीधे पर्वतीय अस्मिता का अंग था जो संस्कृति, बोली, भाषा, जीवन शैली व पहाड़ी परंपराओं से मेल खाता था। पंजाब पुनर्गठन में पहाड़ी लोग तो धकेल दिए, पर्वत का फर्ज, पर्वत का मर्ज, पर्वत की अस्मिता, पर्वत की आत्मनिर्भरता, पर्वतीय क्षेत्रों के समझौते और अनुबंध अपने कब्जे में रख लिए। दूसरी ओर तत्कालीन हिमाचल की शासकीय व्यवस्था ने इन इलाकों को अपनी अस्मिता की भुजा या तर्क बनाने के बजाय, राजनीतिक बंटवारा मान लिया। यही बंटवारा आगे चलकर और अब तक हिमाचल की सियासत को बांट रहा है, वरना पौंग, गोविंदसागर व शानन विद्युत परियोजना जैसे समझौते उसी वक्त हिमाचल की अमानत हो जाते तथा बीबीएमबी का अस्तित्व हमारी पहचान बन जाता।

आश्चर्य यह कि हरियाणा और पंजाब ने केंद्र शासित चंडीगढ़ में अपनी-अपनी राजधानियों की तलाशी में संपत्तियां अर्जित कर लीं, लेकिन किसी सियासी हस्ती ने यह नहीं सोचा कि इसी अनुपात में हिमाचल के हिस्से भी दो-तीन सेक्टर या एक मिनी राजधानी का अधिकार चंडीगढ़ में मिल जाता। हिमाचल अगर चंडीगढ़ में तब अपने लिए भूमि और भूमिका हासिल कर लेता, तो मोहाली व पंचकूला की तरह परवाणू-बीबीएन तक प्रदेश की भी आर्थिक राजधानी होती। हिमाचल ने अपनी सियासी संकीर्णता के कारण पंजाब पुनर्गठन के मसले को सत्ता के लाल कालीन के नीचे छिपाए रखा, फिर भी कुछ मुख्यमंत्रियों ने अस्तित्व की तलाशी में अपने अधिकार खोज डाले। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की यात्रा इन्हीं अधिकारों की खोज थी, तो अब सुखविंदर सुक्खू भी पर्वतीय आत्मसम्मान की बुलंदी को पाने के लिए हुंकारा भर रहे हैं।

राय

हिमाचली पादुका को इंतजार

हिमाचल के लापचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन व सैनिक शिविर में दिवाली का उत्साह सांझा करना, देश के प्रति कत्र्तव्य की एक सुनहरी याद है। सीमांत क्षेत्रों में असामान्य परिस्थितियों में तैनात सैन्य कर्मियों से रूबरू होने की परंपरा में, प्रधानमंत्री का दौरा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, लेकिन कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियों में हिमाचल के भी कई गांव और काम अपने हिस्से की दुरुहता बटोरते हैं। ऐसे में भले ही प्रधानमंत्री का यह दौरा संवेदनशील व सामरिक महत्त्व की प्रतीक्षा को आश्वस्त और सुरक्षा की समीक्षा करता हो, लेकिन प्रदेश हर रास्ते पर अपनी पादुकाएं बिछाए न जाने कब से उनका इंतजार कर रहा है। जब से हिमाचल में डबल इंजन सरकार नहीं रही, पर्वतीय प्रदेश के लिए पीएमओ का व्यवहार और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सरोकार बदल गया है। लापचा कई मायनों में राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यहां पारिस्थितिकीय स्थिति हिमाचल की विडंबनाओं को भी दर्शाती है। बेशक सीमांत क्षेत्रों के गांवों तक भारत सरकार रोड नेटवर्क को सशक्त कर रही है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों से निकलती मौसमी आफत ने हमेशा ही देश के इस भूभाग को डराया है। इस बार की बरसात ने अपनी त्रासदी के भयंकर खंजर हमें दिए हैं, लेकिन दिल्ली से न कोई माकूल चिट्ठी और न ही संदेश आया।

अब भी हमारी दरख्वास्तें, लोगों की चीखें, खेत-बागीचों की बर्बादी का आलम, टूटते पुलों और गायब होती सडक़ की कहानियां केंद्र को अपनी व्यथा सुना रही हैं, लेकिन व्यथा का यह परिदृश्य वहां दिखाई नहीं दिया। लापचा को सरहद पर देखना देशहित का कार्य है, तो लापचा को हिमाचल में देखना भी तो जरूरी है। लापचा में हिमाचल की भी नब्ज टटोली जा सकती थी क्योंकि सीमा की रक्षा में हर दिशा में हिमाचली रक्त भी बहता है। दुश्मन की हर सरहद पर शहादतों का आंकड़ा हिमाचल के हिस्से से लगभग तीस प्रतिशत जोड़ता है, तो इस बहादुरी का अर्थ प्रदेश से मुलाकात करा सकता है। कभी यही किस्से प्रधानमंत्री हिमाचल आकर सुनाते थे। तब सिड्डू भी गर्व महसूस करता था और कांगड़ा की चाय भी रंग जमाती थी। तब हिमाचली संदर्भों की उड़ान वाकई आसमान पर थी, तो क्या अब प्रदेश ने कोई गलती कर दी। क्या जिस जनता के कसीदे तब प्रधानमंत्री कभी मंडी या कभी शिमला में पढ़ा करते थे, वह अब दोषी हो गई। प्रदेश भाजपा की सत्ता से फिसल कर कांग्रेस को क्या मिला, दोषी जनता और जनता के सरोकार हो गए। वे तमाम नदियां दोषी हो गईं जो हिमाचली दर्द को बटोर कर देश के बड़े बांधों के जरिए मैदानी इलाकों को सींचती या बिजली पैदा करके भविष्य को निरंतरता के साथ रोशन करती रही हैं। क्या वे सारी धामें, खाद्य व्यंजन, उपज, तरक्की और राष्ट्र के प्रति हिमाचल का समर्पण भी दोषी हो गया। क्या प्रधानमंत्री के इंतजार में बिछाई गई पादुकाएं सियासी हो गईं या प्राकृतिक आपदा में हिमाचल के आंसू अब बेमतलब हो गए। याद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव से पूर्व दर्जन भर दौरे, संबोधन और आश्वासन जो हमारे हर सूर्योदय में शरीक होते थे, लेकिन अब लगता है कि सियासी ग्रहण से ओतप्रोत भावनाएं, भाव भंगिमाएं दिखा रही हैं। क्या कमाल है देश का संघीय ढांचा और लोकतंत्र का लबादा कि हर हिसाब-किताब, दर्द और इम्तिहान भी चुनावी या सियासी हो गया। क्या सुक्खू सरकार अवैध है कि प्रधानमंत्री अपने रिश्तों की फेहरिस्त भूल गए या हमारा दर्द फर्जी है जो मानवीय चीखें दिल्ली में हार गईं। ऐसे में हिमाचल भाजपा या भाजपा के नेताओं से क्यों न पूछा जाए कि प्रदेश के संघर्ष में उनकी भूमिका आखिर अब है कहां। कल अगर केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में भाजपा की सत्ता आ जाए, तो क्या इसी तरह प्रदेश की फरियाद तहस नहस होती रहेगी। सरकारें आती-जाती रहेंगी और नेता भी बदलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की शर्तों में यह फरेब सही नहीं कि योजनाएं व प्राथमिकताएं अपनी आंखों में भेदभाव का सुरमा लगा कर अन्याय करें। करीब तेरह हजार करोड़ की आपदा हानि के लिए हिमाचल को अगर भाजपा मजबूर देखना चाहती है, तो पढ़े-लिखे नागरिक समाज की भी तौहीन है।

क्रिकेट विश्व कप, सतत पर्यटन व संस्कृति

यहां मैचों के आयोजन से आर्थिकी मजबूत हुई है व प्रदेश को पहचान मिली है'

क्रिकेट विश्व कप के प्रभाव से देश के सरकारी खजाने को अतिरिक्त राजकोषीय वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम तीन महीने के त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। नतीजतन, सम और त्योहारी सीजन खुदरा क्षेत्र को लाभान्वित करेगा और लोगों को 'माल की भावनात्मक खरीद' करने की संभावना है। भारत में आयोजित हुआ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मनोरंजन, भावनाओं और बहुत कुछ का एक रोमांचकारी मिश्रण है। हम इसे 'क्रिकेटोनॉमिक्स' कहते हैं, जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पिच से परे आर्थिक प्रभाव लाता है। विश्व कप 2023 टिकट, स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अनुमान है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 से भारत की अर्थव्यवस्था में 2.6 अरब डॉलर या 22000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में रिपल प्रभाव कई गुना हैं। राजस्व में अल्पकालिक वृद्धि के अलावा खेल आयोजन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के नक्शे पर गंतव्यों को रखने में मदद करते हैं। स्टेडियम की क्षमता, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में निवेश का विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ता है जिससे उन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है। भारत में आयोजित हुए विश्व कप खेल गतिविधियों से उद्योगों में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि वृद्धि हुई है। विशेष रूप से आतिथ्य-होटल, रेस्तरां, खेल और व्यापारिक स्टोर, विदेशों से उत्साही प्रशंसकों को भी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए यात्रा की है।

हिमाचल प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप 2023 के लिए 05 अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन स्थल के रूप में मिला क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला स्टेडियम विश्व सुंदर सुरम्य स्थान है जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आवश्यक पर्यटन स्थल है और साथ ही हमने अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों को स्थानीय खाद्य पदार्थों, संस्कृति, लोककथाओं के साथ-साथ मांझी खड्ड, जल स्नान, ट्रियुंड ट्रेक का आनंद लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंता करते अनुभव किया है। मांझी खड्ड/नदी के आसपास की साफ-सफाई, ट्रियुंड ट्रेक के, रास्ते में ट्रेकर्स द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की वस्तुओं को इक_ा करके सफाई अभियान किया, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाडियों के अनुभव को बढ़ाने की इच्छा के रूप में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अनजाने में एक अधिक सतत यात्रा अनुभव पैदा हुआ। अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों के महान कदम की सराहना की जानी चाहिए। विश्व कप मैच अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों का मुख्य उद्देश्य था। फिर भी वे हिमालय के सबसे सुरम्य हाइकिंग स्थल त्रियुंड की ट्रेकिंग में व्यस्त हो गए और मार्ग में पर्यावरण स्वच्छता अभियान में शामिल हो गए। स्थानीय जीवन शैलियों, सांस्कृतिक प्रशंसा, साथ ही लोक कलाकारों के साथ स्थानीय नृत्य मंच नाटी स्टेप्स को सीखना और रिदम पर नृत्य करना सीखना। खेल, साहसिक कार्य, आध्यात्मिकता, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान, ट्रेकिंग, सांस्कृतिक प्रशंसा, अनुभवात्मक पर्यटन, पारंपरिक गद्दी नाटी और लोकगीत में सक्रिय भागीदारी अनुभव को बढ़ाने की इच्छा के रूप में शुरू हुआ। सतत पर्यटन केवल एक शब्द, चर्चा नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह सोच-समझकर यात्रा करने और पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय समुदायों पर यात्रा प्रभाव को कम करने के बारे में है। यह जिम्मेदार पर्यटन के लिए भी एक अवसर है। यात्रा हमें बदलने का एक अविश्वसनीय तरीका है। यह हमारे क्षितिज को व्यापक बनाता है, हमें विविध संस्कृतियों से परिचित कराता है, और हमारे दिमाग को दुनिया की सुंदरता के लिए खोलता है। जबकि हम अक्सर यात्रा को अपनी दैनिक दिनचर्या से बचने के साधन के रूप में सोचते हैं, यह सामान्य से

सिर्फ एक ब्रेक से अधिक है।

यह एक नई रोशनी में गंतव्यों का पता लगाने की यात्रा है। स्मारक और स्थल एक गंतव्य की कहानी का केवल एक अंश हैं। अधिकांश यात्रा अनुभव प्रसिद्ध पर्यटक हॉटस्पॉट से शुरू होते हैं- प्रतिष्ठित स्थलों, प्रसिद्ध संग्रहालयों और हलचल वाली सडक़ें। जबकि ये आकर्षण निस्संदेह अपना आकर्षण रखते हैं, वास्तविक कथा दैनिक जीवन, परंपराओं और वहां रहने वाले लोगों के सपनों में लिखी गई है। यह एक जगह के सार, इसकी अनूठी कहानियों और उन लोगों के जीवन को उजागर करने के बारे में है जो इसे घर कहते हैं। जबकि भव्य वास्तुशिल्प चमत्कारों को निहारना और ऐतिहासिक स्थलों की खोज निस्संदेह मनोरम है। एक गंतव्य की वास्तविक सुंदरता अक्सर दैनिक जीवन की पेचीदगियों, स्थानीय बाजारों की जीवंतता और इसके लोगों की परंपराओं में पाई जाती है। एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होने के बजाय, संस्कृति में एक सक्रिय भागीदार बनें। स्थानीय लोगों के साथ जुड़ें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें, और उनके जीवन के तरीके के बारे में जानें। पारंपरिक व्यंजनों में महारत हासिल करने के लिए खाना पकाने की कक्षा लें, स्वदेशी संगीत की थाप पर नृत्य करें, और निवासियों के साथ बातचीत करें। ऐसा करने में, आप अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे जो कोई गाइडबुक प्रदान नहीं कर सकती है। स्थानीय कला दीर्घाओं का अन्वेषण करें, परिवार द्वारा संचालित भोजनालयों का दौरा करें, और कारीगर बाजारों के माध्यम से घूमें। समुदाय के साथ जुडऩा वास्तव में परिवर्तनकारी हो सकता है। यात्रा के दायरे में, हम अक्सर खुद को प्रसिद्ध स्थलों का पीछा करते हुए, 'अवश्य देखने' वाले स्थानों पर टिकते हुए और सर्वोत्कृष्ट पर्यटक तस्वीरों को कैप्चर करते हुए पाते हैं।

एक गंतव्य अपने प्रसिद्ध स्मारकों के योग से अधिक है। यह संस्कृति, इतिहास, कला, व्यंजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लोगों को वास्तव में समझने और सराहना करने के लिए, हमें स्पष्ट से परे उद्यम करने और गंतव्य की आत्मा को गले लगाने की आवश्यकता है। यह यात्रा यात्री और खोजे जा रहे स्थान दोनों के लिए अधिक सार्थक और प्रामाणिक यात्रा अनुभव की ओर ले जाती है। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए स्थल सूत्रधार के रूप में बीसीसीआई की भूमिका और इस आयोजन स्थल के रूप में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) का योगदान उल्लेखनीय है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आईसीसी विश्व कप सहित प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंटों की मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थल सुविधा प्रदाता के रूप में, बीसीसीआई विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने, रसद का प्रबंधन करने और भारत में मैचों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) का धर्मशाला में एक विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है, जिसने कई अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है। यहां मैचों के आयोजन से आर्थिकी मजबूत हुई है, हिमाचल को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, पर्यटन का विस्तार हुआ है और हिमाचली संस्कृति का देश-विदेश में प्रचार हुआ है।

डा. अमरीक सिंह ठाकुर

मुझे माफ करना क्रिकेट प्रेमियो!

सच मानिए, जिस तरह वे बिना बैल हल वाले प्रगतिशील किसान हैं, उसी तरह मैं बिना बीवी वाला प्रगतिशील पति हूं। मैं बीवी की वाणी और ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर पूरा पूरा भरोसा करता हूं। बीवी और ज्योतिषी का कहा मेरे लिए परम सत्य है। जिस तरह अंधभक्तों को अपने लोकप्रिय नेता पर अंधविश्वास होता है, उसी तरह मुझे भी अपनी बीवी के वचनों और अपने फैमिली ज्योतिषी के कथनों अंधविश्वास है, दुर्गंध विश्वास है। हालांकि मैं आंखें खुली रखने के बाद भी उनके वचनों के पथ पर चलकर अनेकों बार औंधे मुंह गिर चुका हूं। पता होते हुए भी औंधे मुंह गिरना ही आज सफलता का सूचक है। अबके ज्यों ही मुझ गुल्ली डंडिए की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची तो मैं बीवी के आदेश पर अपने फैमिली ज्योतिषी के पास गया। मैंने उनसे सानुनय पूछा, 'हे हमारे फैमिली ज्योतिषी जी महाराज! अबके मुझे फिर गोल गोल सच बताइए कि विश्व कप कौन जीतेगा?' 'मेरा देश!' अबके उन्होंने बिना आंखें मूंदे ही कहा तो मैं हैरान हो गया। मतलब, वे भी देश को अपना मानते हैं? कल तक तो वे अपने यजमानों को ही अपना मानते थे। यजमान ही उनके भगवान थे। यहां तो केवल चुनाव लडने वाले ही देश को अपना मानते आए हैं। वर्ना मुझ जैसे डेडिकेटिड अफसर तक जिस ऑफिस से हजारों की पगार की आड़ में हर महीने लाखों बटोरते हैं, उस ऑफिस तक को अपना नहीं मानते। पहले तो वे मेरे पूछने पर आंखें मूंद कर हमारी फैमिली का भविष्य बताया करते थे, पर अबके तो उन्होंने आंखें खोले ही पूरे क्रिकेट प्रेमियों का भविष्य बता दिया। बस, फिर क्या था! मैंने दीपावली को आधे पटाखे चलाए और आधे उनके विश्वास में आ विश्व कप की जीत में जश्न में फोडने के लिए बचा लिए। पर मुझ जैसे ढोंगी क्रिकेट प्रेमियों का चाहा कहां हुआ। वे विश्व कप ले गए और हमारे हाथ में प्लेट थमा गए।

मित्रो! अपनी जीत के लिए हर क्रिकेटप्रेमी ने चुनाव में जीत के लिए खड़े उम्मीद्वारों की तरह इनके उनके बताने पर क्या क्या टोटके नहीं किए? पर कोई लाभ न हुआ। उन्होंने हमारी पूजा अर्चना, पर टोटकों पर ऐसा बैट मारा कि हमारी कमर के साथ साथ टोटकों की भी कमर तोड़ दी। शायद भगवान उनकी ही सुनता है जिनके पास हर हाल में जीत की कुंजी होती है। आस्ट्रेलिया की इस न सहन होने वाली हरकत से पूरा देश मौन है। झूठ कहूं तो इसे मेरा देशप्रेम ही कहिए कि इस दुख के बाद मैं भी टूटकर इतना बिखर चुका हूं कि ऑफिस जाने को मन नहीं कर रहा। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। नहाने को मन नहीं कर रहा। बस, मन करता है केवल पीता जाऊं! पीता जाऊं! बॉस से संबंध ठीक होते तो ऑफिस न जाता। हारने के गम में मजे से घर में ही पड़ा रहता। इसलिए जैसे कैसे जो ऑफिस चला ही जाता हूं तो वहां जाकर काम करने को कतई मन नहीं करता। लगता है जैसे सारे हताश निराश क्रिकेट प्रेमी मेरी कुर्सी के आसपास सिसक रहे हों। खैर, काम तो ऑफिस जाने पर मैं पहले भी नहीं करता था। नौकरी आदमी काम करने के लिए थोड़ी करता है।

आराम करने के लिए करता है। काम ही करना होता तो कहीं और काम करता। अपनी हार के बाद मैं कल टुटा लुटा अपने फैमिली ज्योतिषी के पास पुनः गया। हारा हुआ और जीत के लिए आतुर ज्योतिषियों के सिवाय और जा भी कहां सकता है? 'हे मेरे प्रभु! आपकी भविष्यवाणी ने तो मुझे ही मार दिया। तुमने तो कहा था कि ये ये टोटके करो, विश्व कप हमारा होगा।' वे अपनी भविष्यवाणी गलत साबित होने के बाद भी उसी तरह मुस्कुराते बोले, 'कहा था। अपनी बात से मुकर कब कर रहा हूं। पर तुमने मेरे टोटकों का सही पालन कहां किया!

ई-कॉमर्स सेक्टर से सर्विस सेक्टर को मिल रहा है बूस्ट

वित्त वर्ष 26 तक 163 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है कारोबार

वित्त मंत्रालय का मानना है कि देश के सेवा क्षेत्र में ई-कॉमर्स का बड़ा योगदान है और आने वाले दिनों में ई-कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ेगा। सरकारी उपायों के कारण सस्ती कीमतों पर इंटरनेट की उपलब्धता के साथ ई-कॉमर्स व्यवसाय अब टियर 2 और 3 पर पहुंच गया है। वहीं सरकार के इनोवेशन फंड जैसे कार्यक्रम से भी घरेलू ई-कॉमर्स को काफी समर्थन मिला है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय का मानना है कि देश के सर्विस सेक्टर में ई-कॉमर्स अपना अहम योगदान दे रहा है और आने वाले दिनों में ई-कॉमर्स के कारोबार में तेज बढ़ोतरी होगी।

सरकारी नीतियों की वजह से सस्ते दाम पर इंटरनेट उपलब्ध होने से ई-कॉमर्स का कारोबार अब टियर-2 और टियर-3 तक पहुंच गया। वहीं, सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन फंड जैसे कार्यक्रम से भी घरेलू ई-कॉमर्स को काफी समर्थन मिला है।

वित्त वर्ष 26 तक 163 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है ई-कॉमर्स का कारोबार

वित्त मंत्रालय की अक्टूबर की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक ई-कॉमर्स का कारोबार 163 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। किराना बाजार को छोड़ दिया जाए तो अन्य प्रकार की वस्तुओं की 25 प्रतिशत बिक्री अब ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से होने लगी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डाटा की निजता, उपभोक्ता सुरक्षा एवं डिजिटल प्लेटफार्म को लेकर लाए गए नियम से उपभोक्ताओं में ई-कॉमर्स को लेकर भरोसा जगा है और यह कारोबार पारदर्शी होता जा रहा है।

स्मार्टफोन के कारण बढ़ रहा है ई-कॉमर्स

अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता से भी ई-कॉमर्स को मदद मिल रही है। तभी वित्त वर्ष 2022-23 में ई-कॉमर्स के आर्डर वोल्यूम में पूर्व के वित्त वर्ष के मुकाबले 26.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

रिपोर्ट के मुताबिक ई-कॉमर्स से होने वाले कुल कारोबार में टियर-1 की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 में 44.3 प्रतिशत रही। टियर-2 में यह हिस्सेदारी 37.1 प्रतिशत तो टियर-3 में 18.6 प्रतिशत की रही। इसलिए टियर-2 और टियर-3 में ई-कॉमर्स कारोबार के बढ़ने की पूरी गुंजाइश है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा घरों की सजावट, हेल्थ व फार्मा जैसे सेक्टर में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से अधिक खरीदारी हो रही है।

इनमें आई तेजी

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर एफएमसीजी व कृषि, फैशन व गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े उत्पादों की बिक्री में तेजी आई है। ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कई स्टोर अब औमनीचैनल माडल को अपना रहे हैं।

ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूप से कारोबार करने वाले औमनीचैनल की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में औमनीचैनल स्टोर के विस्तार में 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी तरफ, पूरी तरह से ऑफलाइन कारोबार करने वाले कारोबारी सरकार से ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के लिए सख्त नीति लाने की मांग कर रहे हैं ताकि वे किसी वस्तु की बिक्री भारी छूट के साथ नहीं कर सके।

MamaEarth की पेरेंट कंपनी Honasa Consumer ने जारी किए सितंबर तिमाही के नतीजे, 93 प्रतिशत बढ़ा नेट

हाल ही में लिस्ट हुए एफएमसीजी ब्रांड मामाअर्थ और द डर्मा कंपनी के मालिक होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने आज दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। नतीजों के मुताबिक कंपनी का टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट (PAT) करीब दोगुना होकर 29.43 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का PAT 15.19 करोड़ रुपये था।

नई दिल्ली। हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुए एफएमसीजी ब्रांड मामाअर्थ और द डर्मा कंपनी के मालिक होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (Honasa Consumer Ltd) ने आज चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा की। नतीजों के मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्ट टैक्स (PAT) लगभग दो गुना बढ़कर 29.43 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का PAT 15.19 करोड़ रुपये था।

परिचालन से 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा राजस्व

होनासा कंज्यूमर ने बताया कि कंपनी का परिचालन से राजस्व चालू वित्त की दूसरी तिमाही में 20.85 प्रतिशत बढ़कर 496.10 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 410.49 करोड़ रुपये पर था। सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 463.98 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 18.25 फीसदी अधिक है।

21 प्रतिशत से अधिक बढ़ी कुल कमाई

सितंबर तिमाही के नतीजों के मुताबिक कंपनी की कुल आय 21.09 प्रतिशत बढ़कर 503.18 करोड़ रुपये हो गई। मामाअर्थ के अध्यक्ष और सीईओ वरुण अलघ ने कहा, होनासा बाजार में शानदार वृद्धि देने और कंपनी के लाभप्रदता पोर्टफोलियो में लगातार सुधार करने में सक्षम रहा है। वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में हमारा कारोबार साल-दर-साल 33 प्रतिशत बढ़ा है, जो भारत में एफएमसीजी कंपनियों की औसत वृद्धि का 3.8 गुना है।

3.5 प्रतिशत से अधिक टूटा शेयर

आज कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.72 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ। एनएसई पर होनासा कंज्यूमर 13.65 रुपये गिरकर 353.15 पर बंद हुआ।

इनसाइड

दीवाली के बाद महंगा हुआ सोना-चांदी, जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

देश में आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले दिनों देश में धनतेरस और दिवाली के दिन गोल्ड की डिमांड बढ़ गई थी ऐसे में इनकी कीमतों में नरमी देखने का मिली है। अगर आप गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको अपने शहर में सोने की कीमतों के बारे में जान लीजिए।

नई दिल्ली। दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि, दिवाली और धनतेरस के मौके पर इनकी कीमतों में नरमी देखने को मिली थी। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपने शहर में गोल्ड और लेटेस्ट रेट क्या है?

महंगा हुआ सोना

आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 310 रुपये बढ़कर 60,375 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 310 रुपये या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 60,375 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 9,897 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.45 प्रतिशत बढ़कर 1,975.30 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया।

चांदी के दाम चढ़े

बुधवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 598 रुपये बढ़कर 72,191 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, क्योंकि मजबूत हाजिर मांग के कारण प्रतिभागियों ने अपने सौदे बढ़ा दिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 598 रुपये या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 18,241 लॉट में 72,191 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 1.01 प्रतिशत बढ़कर 23.37 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,190 रुपये है।

नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,190 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,580 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

कार्ड Tokenization के साथ आपकी प्राइवेसी को नहीं होता कोई खतरा, जानिए सुरक्षा के लिए कैसे करता है काम

Card Tokenization ऑनलाइन पेमेंट करते समय कई बार फ्रॉड का डर बना रहता है। ऐसे में इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक ने Card Tokenization सिस्टम चालू किया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कार्ड टोकनाईजेशन सिस्टम कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचाता है। इसके अलावा यह कैसे काम करता है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए Card Tokenization सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम का उद्देश्य ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि कार्ड टोकनाइजेशन कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षित रखती है।

कार्ड टोकेनाइजेशन क्या है?

टोकेनाइजेशन एक तरह की सिस्टम है। यह ऑनलाइन पेमेंट के समय डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डाटा को सुरक्षित रखता है। कार्ड टोकेनाइजेशन में क्रेडिट या डेबिट कार्ड में शामिल 16 डिजिट का कार्ड नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट और कोड को सिक्योर किया जाता है। कार्ड क नंबर को एक यूनिक नंबर में बदल दिया जाता है। कार्ड टोकेनाइजेशन से आसानी से थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट से कांटेक्टलैस पेमेंट करने की सुविधा मिलती है।

कार्ड टोकेनाइजेशन सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है। यह ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हो रहे फ्रॉड को एक हद तक कम कर दिया है। उदाहरण के तौर पर कि अगर कभी किसी मर्चेंट की डिटेल्स हैक हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक की जानकारी का भी डाटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कार्ड टोकेनाइजेशन ग्राहक के डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

कार्ड टोकेनाइजेशन कैसे काम करता है?

कार्ड टोकेनाइजेशन में ग्राहक की जानकारी को अल्फानुमेरिक ID में बदल दिया जाता है। इस यूनिक आईडी में ग्राहक की कोई भी जानकारी को शामिल नहीं किया जाता है। अल्फानुमेरिक ID के बारे में बैंक को बताया जाता है कि ग्राहक की जानकारी को कहां पर सुरक्षित किया जाता है। इस टोकन की जानकारी किसी भी मर्चेंट के पास नहीं होती है।

वित्त वर्ष 24 के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पार जाएगी सरकार: सीबीडीटी चेयरमैन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि इस बार सरकार वित्त वर्ष 2024 के लिए निर्धारित 18.23 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को पार कर जाएगी। हाल ही में जारी शुद्ध प्रत्यक्ष कर राजस्व के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 10.6 लाख करोड़ रुपये हो गया।

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि वित्त वर्ष 24 के लिए निर्धारित 18.23 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को इस बार सरकार पार कर जाएगी।

मीडिया से बात करते हुए नितिन गुप्ता ने बताया

हम बजट लक्ष्य को पार कर जायेंगे। अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और 15 दिसंबर तक अग्रिम कर संख्या की तीसरी किस्त आने के बाद हमें पूरे साल के कर संग्रह की बेहतर तस्वीर मिलेगी।

कितना रहा था नेट डायरेक्ट कलेक्शन?

हाल ही जारी हुए नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मुताबिक इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22 प्रतिशत बढ़कर 10.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

नितिन गुप्ता ने बताया सकल आधार पर, प्रत्यक्ष कर संग्रह 17-18 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि शुद्ध आधार पर, हम 22 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। हम साथ-साथ रिफंड भी जारी कर रहे हैं। इसलिए, हमें अनुमान से अधिक कर संग्रह होने में कोई संदेह नहीं है

कितने करोड़ का रिफंड हुआ जारी?

आंकड़ो के मुताबिक 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच कुल 1.77 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं। 2023-24 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 16.61 लाख करोड़ रुपये से 9.75 प्रतिशत अधिक है।

अभी-अभी घर में गूंजी हैं किलकारियां, लेने का है प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान

परिवहन विशेष न्यूज

Health Insurance Plan हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी है। यह मेडिकल खर्चों को कम करने में मदद करता है। वहीं यह फैमिली की सुरक्षा करने में भी काफी मदद करते हैं। आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को भी हेल्थ इंश्योरेंस में सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप अपने बेबी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।

नई दिल्ली। हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) में अपने पूरे परिवार को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको अपने नवजात शिशु को भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करना चाहिए। यह काफी जिम्मेदारी वाला काम है। ऐसे में आप अपने बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करके अपनी जिम्मेदारी को आसान से पूरा कर सकते हैं।

आप अपने बच्चे को फैमिली फ्लोटर या फिर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

हेल्थ पॉलिसी

कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 90 दिनों के बाद ही नवजात शिशु को हेल्थ पॉलिसी देते हैं। वहीं कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पहले दिन ही नवजात शिशु को हेल्थ पॉलिसी में सिक्योर कर देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस 90 दिन के बाद शुरू होगा या फिर जन्म के साथ एक्टिव होगा।

रिन्यूअल

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को साल में एक बार रिन्यू करवाना होता है। आप जब हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते हैं तब आप अपने बच्चे को शामिल कर सकते हैं। आप जब भी रिन्यू फॉर्म भरते हैं तो आपको सारी जानकारी देनी होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगी कि आप रिन्यू के समय पर सभी डॉक्यूमेंट होंगे। अगर कंपनी जन्म लेते ही बच्चे को कवर करती हैं तो आपको उसकी जानकारी 7 दिन के भीतर कंपनी को देना होता है।

डॉक्यूमेंट

बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको सही डाक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आप पॉलिसी लेते समय सभी डॉक्यूमेंट को सही समय पर अपलोड करें। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय एक बार प्रीमियम को जरूर चेक करना चाहिए।

नियम व शर्तें

हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करते समय नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप ध्यान रखें कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आपको कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही है। कई बार हम नियम व शर्तों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे में भविष्य में हमें इस से परेशानी होती है।

मतगणना से पहले एक्शन में कांग्रेस, विश्वासघात करने वालों की हो रही पहचान

परिवहन विशेष न्यूज

कांग्रेस ने बस्तर में पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल झज्ज, विक्रम शर्मा को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अनूप नाग को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है...

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में दो चरणों में सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान भितरघात करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ-साथ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भितरघात करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो कुछ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी व अन्य दलों से चुनाव लड़ने वालों को पार्टी से छह साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है।

कांग्रेस ने बस्तर में पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल झज्ज, विक्रम शर्मा को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अनूप नाग को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा पुष्पा पाटले, तारकेश्वर गाभेल और त्रिलोक श्रीवास को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। पार्टी करीब दो दर्जन से ज्यादा बागी नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है।

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगी, लेकिन बाकी लोगों को मिलकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ेगा, तो कार्रवाई तो होगी ही। इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जीतकर आ रही है। पार्टी के पास और भी शिकायतें आई हैं। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

प्रभारी शैलेजा ने की वन-टू-वन चर्चा

बीते शनिवार और रविवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दो दिन तक प्रदेश के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से वन-टू-वन चर्चा की थी। विधायकों से भी चुनाव की स्थिति की टोह लेती रहीं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शैलजा ने सीधे-सीधे पूछा है कि क्या आप चुनाव जीत रहे हैं? जीत रहे हैं तो जीत का अंतर क्या होगा? अगर हार गए तो किसकी वजह से हारेंगे? किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया? कुछ प्रत्याशियों ने शैलजा को भितरघात करने वालों की नाम के साथ शिकायत की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 30 फीसदी सीटों पर बागियों ने पार्टी के विरोध में प्रचार-प्रसार व अन्य गतिविधियां की हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी ने अब तक 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर भितरघात करने वाले करीब 50 नेताओं पर निष्कासन, निलंबन व अन्य कार्रवाई की है। वहीं आधा दर्जन से अधिक नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।

उत्तरकाशी टनल हादसा: सुरंगों के जाल में फंसता जा रहा पर्वतराज हिमालय

विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी क्षेत्र की जनता को विकास भी चाहिए तभी उनकी जिंदगी की मुश्किलें कम होंगी और बेहतर जीवन सुलभ होगा। हिमालय वासियों के लिए सड़कें भी चाहिए, तो बिजली-पानी और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन पहाड़ों पर सड़कें बनाना तो आसान है मगर उन सड़कों के निर्माण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना उतना आसान नहीं है।

पौराणिक नगरी जोशीमठ के धंसने के कारण तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना की सुरंग के चर्चा में आने के बाद चारधाम सड़क परियोजना की उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा परियोजना की सुरंग के एक हिस्से के धंसने से वहां फंसे 41 मजदूरों की जान संकट में पड़ने के बाद एक बार फिर विश्व की सबसे युवा पर्वत माला हिमालय में सुरंगों के निर्माण पर सवाल उठने लगे हैं।

सुरंगों सहित भूमिगत निर्माण में इस तरह के हादसे नए नहीं हैं। अब तो सुरंगों के धंसने और निर्माणाधीन सुरंगों के ऊपर बसी बस्तियों के धंसने की शिकायतें आम हो गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में इस वक्त पौने तीन लाख करोड़ रुपये की लागत की टनल बनाई जा रही हैं। अगर सिलक्यारा सुरंग की ही तरह सभी सुरंगें बनाई जा रही हैं तो हिमालय और हिमालय वासियों का ऊपरवाला ही मालिक है।

बांधों के बजाय सुरंगों के जरिए बिजली

विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी क्षेत्र की जनता को विकास भी चाहिए तभी उनकी जिंदगी की मुश्किलें कम होंगी और बेहतर जीवन सुलभ होगा। हिमालय वासियों के लिए सड़कें भी चाहिए, तो बिजली-पानी और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन पहाड़ों पर सड़कें बनाना तो आसान है मगर उन सड़कों के निर्माण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना उतना आसान नहीं है। तेज ढलान के कारण पन बिजली उत्पादन के लिए हिमालयी क्षेत्रों को सबसे अनुकूल माना जाता है।

इसीलिए नीति नियन्ताओं और योजनाकारों की नजर हिमालय पर पड़ी है। पन बिजली पैदा करने के लिए ग्रेविटी या ढलान की आवश्यकता होती है ताकि तेज धार या पानी की भौतिक ऊजा से पावर हाउस की टरबाइन चल सकें और फिर बिजली का उत्पादन हो सके। इसके लिए पहाड़ों से बहने वाली नदियां ही सबसे माकूल हैं।

इन नदियों का वेग और भौतिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए पानी को तेज ढलान वाली सुरंगों से गुजारा जाता जिसके लिए पहाड़ी क्षेत्र ही सबसे अनुकूल होते हैं। मैदानी क्षेत्र में पानी के लिए इतनी ढाल या ग्रेविटी के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र डुबोना होता है। इसलिए अब तक जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक पन बिजली के लिए योजनाकारों ने हिमालयी क्षेत्र को चिन्हित कर रखा है।

अब यातायात और पार्किंग के लिए भी सुरंगें

हिमालय पर सुरंगों का निर्माण शुरू से चर्चा का विषय रहा है। हिमालय के गर्भ को छलनी करने का समर्थन तो पर्यावरणविद कर नहीं सकते मगर भूविज्ञानी भी इसमें संयम की सलाह अवश्य देते हैं। वर्तमान में हिमालय पर केवल बिजली परियोजनाओं के लिए नहीं बल्कि यातायात और अन्य गतिविधियों के लिए भी सुरंगों का निर्माण हो रहा है।

पहले भूमिगत बिजली घर बने लेकिन अब तो पहाड़ी नगरों में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भूमिगत पार्किंग भी बनने लगी हैं। राज्य गठन से पहले ही अकेले उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर रोड़ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंगों के अलावा लगभग 750 किमी लम्बी सुरंगें विभिन्न चरणों में थीं। अब प्रस्तावित सहित कुल सुरंगों की लम्बाई हजार किमी से ज्यादा हो गई है।

जोशीमठ जैसे नगर भुगत रहे सुरंगों का अंजाम

एनटीपीसी की लगभग 12 किमी लम्बी सुरंग को जोशीमठ के धंसने के लिए पर्यावरणविद जिम्मेदार मानते रहे हैं। जोशीमठ के ही सामने चाईं गांव के धसने के लिए 300 मेगावाट की विष्णु प्रयाग परियोजना की 13 किमी लम्बी सुरंग पर ऊंगलियां उठती रही हैं। पेशे से इंजिनीयर रहे भारत के दूरदृष्टा सिचाईं और ऊर्जा मंत्री रहे के. एल. राव द्वारा देश के जल संसाधनों का सन-60 के दशक में व्यापक सर्वेक्षण कराया गया था। उसी सर्वेक्षण के आधार पर भाखड़ा नागल बांध से लेकर टिहरी बांध जैसी परियोजनाएं शुरू हुई थीं।

उसी के आधार चिन्हित परियाजनाएं आज विभिन्न चरणों में हैं। जिनमें कुछ हरित प्राधिकरण द्वारा रोकी भी गई है। इनमें लगभग कुल 750 किमी लम्बी सुरंगें विभिन्न चरणों में हैं। नाथपा झाकड़ी की 27.40 किमी, नगनादी अरुणाचल की 10 किमी, दुलहस्ती चेनाब की 10.60 किमी और लोकतक मणिपुर की 6.88 किमी लम्बी सुरंगें तो बहुत पहले ही बच चुकी थी। एक सुरंग खोदने के लिए कई सुरंगें बनानी होती हैं। हालांकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में पैसे बचाने के लिए अतिरिक्त सुरंगें नहीं बनाई गई।

सैकड़ों किमी सुरंगें पहले ही बन चुकीं हिमालय पर

वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियालाजी के पूर्व निदेशक एनएस विरदी और एक अन्य भू-वैज्ञानिक ए.के. महाजन के एक शोध पत्र के मुताबिक अकेले गंगा वेसिन की प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 150 किमी लंबी सुरंगें खुद रही हैं या खोदी जा चुकी हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं में से विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट पर 12 किमी सुरंग चल रही है।

भागीरथी पर बनने वाली परियोजनाओं में लोहारी नागपाला 13.6 किमी, पाला मनेरी 8.7 किमी व मनेरी भाली द्वितीय में 15.40 किमी लंबी सुरंग शामिल है। मनेरी भाली प्रथम में पहले ही 9 किमी लंबी सुरंग काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी की 27.40 किमी, देहरादून की छिबरो पावर हाउस की 5.7 किमी, नगनादी अरुणाचल की 10 किमी दुलहस्ती चेनाब की 10.60 किमी और मणिपुर के लोकतक की 7 किमी जैसी कई सुरंगें पहले ही बन चुकी हैं।

राजद्रोह पर IPC प्रावधानों के खिलाफ अर्जी पर जनवरी में 'सुप्रीम' सुनवाई, PMLA केस पर कही यह बात

राजद्रोह पर आईपीसी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी माह में सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह पर आईपीसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई होगी। बता दें कुछ माह पहले केंद्र द्वारा दंडात्मक कानूनों में बदलाव करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया था, जिसमें राजद्रोह कानून को निरस्त करने का जिक्र था।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन किया जाएगा। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें कहा था कि याचिकाओं को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास न भेजा जाए।

बता दें 11 अगस्त को आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए केंद्र ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। जिसमें राजद्रोह कानून को निरस्त करने और कानून पेश करने का प्रस्ताव था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 11 मई को राजद्रोह पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक इसकी उचित जांच नहीं कर लें। साथ ही केंद्र और राज्यों को इस प्रावधान के इस्तेमाल करने के लिए नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आदेश दिए थे।

पीएमएलए मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीमित दायरा यह कि क्या 2022 के फैसले पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। बता दें 2022 के फैसले में प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन में शामिल संपत्ति में गिरफ्तारी करने और कुर्क करने की शक्तियों को बरकरार रखा था। मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीएमएलए देश के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था। याचिकाकार्ता ने दावा किया था कि ईडी 'बेकाबू घोड़ा' बन गया है, जहां चाहे वहां जा सकता है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ कुछ मापदंडों पर तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 27 जुलाई, 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समीक्षा करने की आवश्यकता है या नहीं, यह सीमित दायरा है। पीठ ने कहा, हमें यह भी देखना होगा कि क्या मामले को पांच जजों के पास भेजने की जरूरत हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह मुद्दा 'कानून के शासन' के लिए मौलिक है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हालांकि मामले में दलीलें बेनतीजा रही। गुरुवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परिसीमन आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए

लिम्बु और तमांग आदिवासियों के लिए परिसीमन आयोग के पुनर्गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए लिम्बु और तमांग समुदायों की मांग का एक संवैधानिक आधार है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन समुदायों को 2012 में अनुसूचित जनजाति में नामित शामिल किया गया, उनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। कोर्ट ने हालांकि हम संसद को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। हमारा विचार है कि इन समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए।

साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चर्चा करने और गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र के तर्क को भी अस्वीकार करते हुए कहा, 2026 की जनगणना होने तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, यह कब किया जाएगा? 2031 में? इन समुदायों को आरक्षण पाने के लिए अगले आठ वर्षों तक इंतजार करना होगा। आप दो दशक पीछे हैं। आप संवैधानिक जनादेश से इनकार कर रहे हैं।

ईडी का दावा- कांग्रेस उम्मीदवर के ठिकानों से जब्त दस्तावेजों में करोड़ों के बेहिसाब लेनदेन के संकेत

पूर्व सांसद विवेक वेंकटस्वामी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर राजनेता हैं। उन्होंने अपनी 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर तीस नवंबर को मतदान होगा।

तेलंगाना की विवेक वेंकटस्वामी के खिलाफ तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये के संदिग्ध और बेहिसाब लेनदेन का संकेत देने वाले दस्तावेज जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह दावा किया। वेंकटस्वामी चेन्नूर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मंगलवार को हैदराबाद में कांग्रेस नेता के आवास पर छापेमारी की गई। इसके अलावा, हैदराबाद में उनकी कंपनी विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यालय परिसर और रामागुंडम में विजिलेंस सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मंचेरियल जिले के हाईटेक सिटी में उनके अस्थायी निवास की भी तलाशी ली गई।

पूर्व सांसद वेंकटस्वामी (65 वर्षीय) तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर तीस नवंबर को मतदान होगा।

वेंकटस्वामी ने इस महीने की शुरुआत में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और हैदराबाद में पार्टी नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह पहले कांग्रेस में ही थे, जहां से वह बीआर और फिर भाजपा में चले गए थे।

ईडी को जानकारी मिली थी कि विवेक (जिन्हें डॉक्टर गद्दाम विवेकानंद के रूप में भी जाना जाता है) के बैंक खाते से विजिलेंस सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड के साथ आठ करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। इसके बाद जांच के लिए एजेंसी ने छापेमारी शुरू की। एजेंसी ने दावा किया, विजिलेंस सिक्योरिटी के बैंक खाते का इस्तेमाल बिना किसी वास्तविक कारोबार के पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था और विवेक, उनकी पत्नी व उनकी कंपनी विसाका इंडस्ट्रीज का विजिलेंस सिक्योरिटी के साथ सौ करोड़ रुपये से ज्यादा लेन-देन था। इसने आगे कहा, तलाशी अभियान में डिजिटल उपकरण और करोड़ों रुपये के संदिग्ध व बेहिसाब लेन-देन का संकेत देने वाले दस्तावेजों को जब्त किया गया है। संपत्ति के सौदों में बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने कहा कि जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि समूह की कंपनियों के भीतर बड़े पैमाने पर अंतर-कंपनी जमा राशियां (इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट्स) हैं, जिनका कोई वैध कारोबार नहीं है, लेकिन उनके पास बड़े पैमाने पर जमीन की संपत्ति है।

'पनौती' वाले बयान पर सियासत तेज, भाजपा ने जताया विरोध; EC से राहुल-खरगे के खिलाफ कार्रवाई की मांग

चुनाव आयोग को भेजे पत्र में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि लगातार फर्जी, आधारहीन और अपमानजनक व्यवहार के लिए मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'पनौती' वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसको लेकर बुधवार को अपना विरोध जताया और चुनाव आयोग (ईसी) से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एक अन्य पदाधिकारी ओम पाठक समेत भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने उन पर यह झूठा दावा करने का आरोप लगाया कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी जाति गुजरात की ओबीसी सूची में शामिल की गई थी।

ओम पाठक ने कहा कि घांची जाति को 1999 में ओबीसी सूची में शामिल किया गया था, जबकि मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव आयोग को भेजे पत्र में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि लगातार फर्जी, आधारहीन और अपमानजनक व्यवहार के लिए मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप करें और उन पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पारित करें।

पत्र में आगे कहा गया, अन्यथा यह चुनावी माहौल को खराब करेगा और असभ्य व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने और झूठी खबरें फैलाने के लिए किया जाएगा। अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी भाषण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था।

'पनौती' शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो बुरी किस्मत को लाता है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें एक 'विवेकहीन और मूल्यहीन' राजनेता बताया और कहा कि पीएम मोदी का विश्व के नेता सम्मान करते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023